दैनिक साधना एक्सप्रेस

वर्ष-4 | अंक -191 | sadhnaexpress@gmail.com | भोपाल, शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य - 2 रुपये | www.sadhnaexpress.com

न्यूज ब्रीफ

सीएम थलपति विजय को झटका! हाई कोर्ट में खुलासा- लीक होने के कारण 1.2 करोड़ लोग देख चुके हैं 'जन नायकन'

नई दिल्ली, एजेंसी | थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' जहां एक ओर अभी भी सेंसर बोर्ड में रिलीज के लिए अटकी हुई है, वहीं कथित तौर पर फिल्म लीक केस में एक और बड़ा मोड़ आया है। चेन्नई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफाइड होने से पहले यह ऑनलाइन कैसे लीक हो गई है। गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए लीक मामले में आरोपी का जमानत देने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लीक होने के कारण लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने 'जन नायकन' देख ली है।

मद्रास हाई कोर्ट ने 'जन नायकन' लीक मामले में 2 जुलाई को आरोपी एस. रजनी, जयप्रकाश और 11वें आरोपी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही लगभग 1.2 करोड़ लोगों इसे ऑनलाइन देखा था, जिससे यह हाल के वर्षों के सबसे बड़े पाइरेसी मामलों में से एक बन गया है।

मुख्य आरोपी एक फ्रीलांस फिल्म एडिटर है, उसने एडिटिंग स्टूडियो से फिल्म की फाइलें हार्ड ड्राइव में कॉपी की थीं। उसने इन फुटेज को एक पूरी फिल्म में बदला और गूगल ड्राइव पर अपलोड किया, जहां से यह पाइरेसी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचीं।

दिल्ली दहलाने की साजिश फिर नाकाम: शहजाद भट्टी के संपर्क में थे पकड़े गए आतंकी, सामने आया तुर्किये कनेक्शन

नई दिल्ली, एजेंसी | दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने की नापाक साजिश को नाकाम किया है। टीम ने इस संबंध में आईएसआई टेरर मॉड्यूल के चार आतंकियों को पंजाब और दिल्ली से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। पकड़े आतंकी शहजाद भट्टी और उसके हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। मॉड्यूल के लिए आईएसआई ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते भारत में लगातार हथियार और ड्रग्स भेज रही है।

पकड़े गए आतंकियों की पहचान तरनतारन, पंजाब निवासी शुभदीप सिंह उर्फ विशाल (23), गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि (22), अमृतसर, पंजाब नि वासी साजन सिंह उर्फ हनी (28) और फतेहगढ़ साहिब, पंजाब निवासी गगनप्रीत (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक तुर्किये निर्मित जिगाना पिस्टल समेत दो पिस्टल, 9 कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

गगनप्रीत के मोबाइल से पुलिस को कई धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों के अलावा पुलिस के कई दूसरे भवनों की वीडियो मिली है। गगनप्रीत दिल्ली में रहकर लगातार रेकी के वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेज रहा था। पकड़े गए आरोपियों में शुभदीप व गुरजंत दोनों सगे भाई हैं। पुलिस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

कम पानी और कम अवधि वाली फसलें अपनाने के लिए किसानों को करें प्रेरित

संभावित अल्प वर्षा से निपटने के लिए सभी विभाग करें समन्वित तैयारी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

• भोपाल संवाददाता

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संभावित अल्प वर्षा की स्थिति को चुनौती नहीं, बल्कि बेहतर योजना, वैज्ञानिक खेती और समयबद्ध तैयारी के अवसर के रूप में लिया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं, जिससे प्रदेश में कृषि उत्पादन और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में इस वर्ष प्रदेश में संभावित अल्प वर्षा की स्थिति के मद्देनजर किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जल संसाधन, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य संबंधित विभागों की अब तक की पूर्व तैयारियों की गहन समीक्षा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश का प्रत्येक किसान मौसम की चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच और उचित तैयारी के साथ करे। समय पर सही निर्णय और विभागों के प्रभावी समन्वय से हम संभावित अल्प वर्षा के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कम पानी और कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की खेती के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। उन्होंने ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर तथा कोदो-कुटकी जैसी मोटे अनाज एवं दलहनी फसलों को अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ये फसलें कम पानी में भी बेहतर

उत्पादन देने के साथ किसानों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को जल्दबाजी में बुआई नहीं करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। खेतों में पर्याप्त नमी आने के बाद ही बुआई की जाए तथा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं। साथ ही कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों के सुझावों को प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाया जाए, जिससे वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त फसल का चयन कर सकें। इसके लिए कृषि विस्तार तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार संभावित अल्प वर्षा की स्थिति पर सतत निगरानी रखे हुए है। सभी संबंधित विभाग पूर्व नियोजित कार्य योजना के अनुसार समन्वित रूप से कार्य करें और किसानों को हर संभव तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है और उनकी समृद्धि तथा कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी।

रक्षा, ऊर्जा, एआई में भारत-जापान के बीच हुए बड़े समझौते, पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची को बताया अपनी छोटी बहन

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | भारत और जापान ने रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों (MoC) पर हस्ताक्षर किए. नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की मौजूदगी में हुए इन समझौतों को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' बताते हुए दोनों देशों के रिश्तों को भरोसे और मित्रता की मिसाल करार दिया.

दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की मौजूदगी में कई मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन (MoC) पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों का उद्देश्य रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक और

अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है.

दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और गहरा करने, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI और उभरती हुई तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई. इन समझौतों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले G7 शिखर सम्मेलन में भी कहा था कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल के दौर में आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है. उन्होंने कहा, 'मुझे गर्व है कि भारत-जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है.'

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में जापान ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसी सहयोग ने दोनों देशों के बीच विश्वास और दोस्ती का मजबूत रिश्ता बनाया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की यह यात्रा भारत-जापान की स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के एक नए अध्याय की शुरुआत है.

उपचुनाव का बिगुल! चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों के लिए किया तारीखों का ऐलान

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | देश के तीन प्रमुख राज्यों— बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज होने वाली हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इन राज्यों की तीन रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सभी सीटों पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती और नतीजों का ऐलान 3 अगस्त को किया जाएगा। जिन तीन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीट शामिल है।

बांकीपुर विधानसभा – बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनाव भाजपा (BJP) नेता नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हो रहा है। नितिन नवीन को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे अब राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने विधानसभा सदस्यता छोड़ दी थी। गौरतलब है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी को 51,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी थी।

दतिया विधानसभा – मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। यह सीट कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई है। राजेंद्र भारती ने 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराकर उलटफेर किया था।

मंजलपुर विधानसभा– गुजरात के वडोदरा क्षेत्र की मंजलपुर सीट पर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के दुखद निधन के कारण हो रहा है। योगेश पटेल ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तशवीन सिंह को 1 लाख से अधिक मतों के रिकॉर्ड अंतर से पराजित किया था।

ममता बनर्जी से छिनेगी टीएमसी ? चुनाव आयोग से मिला बागी सांसदों का गुट, दो-तिहाई एमएलए के समर्थन का दावा

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. गुरुवार (2 जुलाई) को तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और दो-तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा किया है.

EC से मुलाकात के बाद रितब्रत बनर्जी ने कहा, '22 जून को कोलकाता में हमारे डेलीगेशन की बैठक हुई थी. उसमें नेशनल कमेटी चुनी गई, हमने 23 जून चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी दे दी और चुनाव आयोग से मांग की थी कि यह हमको मिलने का मौका दिया जाए. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो तिहाई से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, पार्षद, जिला परिषद सदस्य सब हमारे साथ हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'हमारी लड़ाई उस कल्चर के खिलाफ है, जिसमें जमीन स्तर पार्टी को एक परिवारवाद की पार्टी बना दिया, तानाशाही के खिलाफ है लड़ाई. हमारी लड़ाई सिंडिकेट चलाने वालों के खिलाफ है. यह जो नतीजा है वो करप्शन के खिलाफ है.' बनर्जी ने पार्टी में टूट को लेकर कहा, 'तृणमूल कांग्रेस में टूट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि असली तृणमूल कांग्रेस तो हम ही हैं. हमने चुनाव आयोग को यह बताया है, ममता बनर्जी क्या कहती हैं अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है. हमने 23 जून को ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसके बारे में बता दिया था.'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय और अनिल को ट्रस्ट देगा कारण बताओ नोटिस

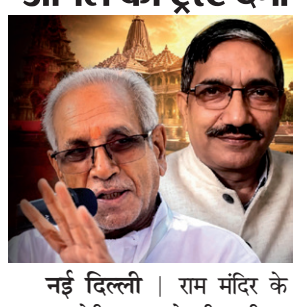

नई दिल्ली | राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की छह जुलाई को प्रस्तावित बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को बैठक में कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया जाएगा।

दोनों से प्रकरण पर लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ट्रस्ट अपने बायलॉज और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आगे का फैसला करेगा।

ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के बायलॉज के तहत किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ बिना स्पष्टीकरण लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, फिर संबंधित पदाधिकारी का जवाब सुना और रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

सिया को लेकर घर पहुंची पुलिस, बरामद किए अहम सबूत

पुणे, एजेंसी | पुणे के बिजनेसमैन और रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में एक अहम मोड़ आया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने गुरुवार को वे कपड़े बरामद किए, जो मुख्य आरोपी सिया गोयल ने घटना वाले दिन पहने थे। ये कपड़े सिया के घर से ज़ब्त किए गए हैं और अब इन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि इन कपड़ों पर ऐसा कोई वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद है या नहीं, जिससे हत्या की पूरी वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सकें। गुरुवार सुबह पुलिस की एक टीम सिया को उसके घर लेकर गई, जहां तलाशी के दौरान ये कपड़े बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार, फॉरेंसिक जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन कपड़ों से हत्या से जुड़े कोई महत्वपूर्ण सबूत मिलते हैं या नहीं। यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है, जब पुणे ग्रामीण पुलिस इस पूरे मामले को सुनियोजित साजिश मानकर जांच कर रही है।

अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक्शन, आईएनएस त्रिकंद ने समुद्री लुटेरों के हमले को किया नाकाम

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने बीती रात अदन की खाड़ी में एक बड़ी बहादुरी दिखाते हुए समुद्री डाकुओं के हमले को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, डाकुओं ने एमवी गोल्डन आर्सेनल नाम के एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था, जिसे भारतीय नौसेना ने समय रहते बचा लिया।

जहाज पर हमला होते ही चालक दल के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाई और खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत रेडियो संचार के जरिए नौसेना को इस हमले की जानकारी दी। इस जहाज पर एक भारतीय चालक दल का सदस्य भी मौजूद था और जहाज भारत के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण सामान लेकर आ रहा था।

जैसे ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद तेजी से संकट में फंसे जहाज की तरफ बढ़ा, उसे आता देख समुद्री डाकू डरकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद नौसेना के घातक मार्कोस कमांडोज जहाज पर उतरे और पूरे जहाज की बारीकी से जांच की ताकि यह पक्का किया जा सके कि वहां अब कोई खतरा नहीं है। कमांडोज की इस मुस्तैदी से जहाज और उसके सभी सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं।

इतिहास

मुंबई में खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के असलम शेख की मौत, ठेकेदार के खिलाफ दर्ज होगा मामला

• मुंबई, एजेंसी

मुंबई | मुंबई में लगातार भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरकर बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. चांदीवली इलाके में जलभराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चल सका और वह उसमें गिरकर बह गया. अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज एवं बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया. उपमहापौर संजय घाडी ने कहा कि इस मामले में संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने ठेकेदार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे "गैर-इरादतन हत्या" का मामला बताया.

कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है. आम लोगों की जिंदगी से इनको कोई लेना देना नहीं है. इनको बस सत्ता चाहिए. पहले एक बस पर पेड़ गिरने से निर्दोष बच्चे की मौत हो गई और आज इनके 'विकास' का दूसरा नजारा सामने आया है. सरकार के भ्रष्टाचार की सीमा खत्म हो गई है. सरकार को लगता है कि हमार कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है.

इस घटना पर शिंदे गुट के नेता दिलीप मामा लांडे ने कहा कि एक मैनहोल में गिरकर मौत हुई और अगले मैनहोल से शव बरामद हुआ. पुलिस और बीएमसी उसकी जांच कर रही है. जिसकी जिम्मेदारी सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चेंबूर में बस के ऊपर पेड़ गिरने की घटना पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से बीएमसी जिम्मेदार है. बीएमसी के लोगों को स्थानीय लोगों ने पेड़ के बारे में बताया था लेकिन बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की.

रजरप्पा मंदिर का बदलेगा स्वरूप: हाईकोर्ट के निर्देश पर अब QR कोड और दानपेटी की सुविधा, जल्द बनेंगी 254 दुकानें

रांची, एजेंसी | झारखंड के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर परिसर की व्यवस्था और सूरत को पूरी तरह संवारने की तैयारी चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार और रामगढ़ प्रशासन लगातार सीसीएल के साथ मिलकर मंदिर के विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। रजरप्पा मंदिर कॉरिडोर और विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसकी कुल राशि 250 से 300 करोड़ रुपये रहने की संभावना है। दरअसल, संजीव कुमार सिंह की ओर से रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की ओर से रजरप्पा मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने को लेकर पूर्व में ही विस्तृत आदेश दिया गया था। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाने पर याचिकाकर्ता संजीव कुमार सिंह की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इस याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई रि मंदिर में चढ़ावे और पैसों के हेरफेर को रोकने के लिए जल्द ही दानपेटियां रखी जाएंगी।

जल ही जीवन है, इसका संरक्षण और संवर्धन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : प्रभारी मंत्री

– प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में ग्राम घिचलाय में आयोजित हुआ 'जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन एवं सम्मान समारोह

देवास। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के मुख्य आतिथ्य में देवास जिले में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' का समापन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम सोनकच्छ जनपद पंचायत के ग्राम घिचलाय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने जल संरक्षण के महत्व पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और इसके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। उन्?होंने कहा कि 'जब हम जल संकट से जूझते है, तब हम एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, परंतु जब पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो अक्सर नल चालू छोड़कर व्यर्थ जल बहाया जाता है। हमें इस मानसिकता को बदलने की सख्त जरूरत है। उन्होंने सभी से जल संरक्षण की अपील की। प्रभारी मंत्री श्री देवडा ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। प्रभारी मंत्री श्री देवडा ने 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत ग्राम में बनाये गये तालाब का अवलोकन भी किया।

प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए जल संरक्षण के लिए तालाब, बावड़ी और कुओं जैसी संरचनाओं का निर्माण किया था। केंद्र और राज्य सरकार इन अमूल्य धरोहरों को सहेजने एवं इनके जीर्णोद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इन पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि गांवों में तालाबों का होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए बेहद लाभदायक है। इससे कृषि, पशुओं और नागरिकों को पानी की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उन्होंने अभियान के अंतर्गत निर्मित किए गए तालाबों के कार्य को बेहद सराहनीय और अनुकरणीय बताया। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान पर जोर देते हुए कहा कि सभी नागरिक अभियान से जुड़कर अनिवार्य रूप से पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी संकल्प ले कि स्वयं एक पेड़ लगाने के साथ-साथ अन्य नागरिकों को भी इस अभियान के तहत पौधारोपण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि तन, मन, धन सभी से ऊपर वन है। यदि पेड़ होंगे तभी हम सांस ले पाएंगे और जल होगा तभी हम जीवित रह पाएंगे।' उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा 'हर घर नल से जल' पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जल संरक्षण के लिए आगे आएं और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए पानी की एक-एक बूंद को बचाएं। सोनकच्छ विधायक डॉ राजेश सोनकर ने कहा कि जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पानी की एक-एक बूंद को सहेजने और जल स्रोतों के संरक्षण का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय और जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि 'जल बिन सब सून है', इसलिए इस सिद्धांत को हमें केवल नारों में नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना होगा। हम सभी को अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के लिए आगे आकर जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सोनकच्छ विधानसभा के 52 गांवों को नर्मदा परियोजना से जोड़ा गया है। इन सभी गांवों में नर्मदा का पानी दिया जाएगा। किसान भाइयों के जीवन को खुशहाली में बदलने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर चलते हुए हर नागरिक के जीवन को सुगम और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि जिले में पिछले दो महीनों से 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया गया। जिले में जल संचय को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है, अभियान के दौरान हजारों नई जल संरचनाओं का निर्माण और पुरानी संरचनाओं का पुनरुद्धार किया गया है। इसके साथ ही जन कल्याण शिविरों का आयोजन कर जिले के 50 हजार से अधिक नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया।

'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को किया सम्मानित

कार्यक्रम में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत घिचलाय, अगेरा, खजुरिया कंका, कुमारा बनवीर, चौबारा जागीर, खेरिया जागीर, चांदाखेडी, जामगोद के सरपंच-सचिव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरूलाल अटरिया, पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव, बहादुर सिंह पिलवानी, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि, नगर परिषद के प्रतिनिधि, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद, सीईओ जिला पंचायत ज्योति शर्मा, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, एसडीएम सोनकच्छ आनंद मालवीय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

जल की प्रत्येक बूंद का संचय जरूरी: मंत्री दिलीप जायसवाल

– ग्राम औढ़ेरा में जल गंगा संवर्धन अभियान का जिला स्तरीय समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मंत्री दिलीप जायसवाल

अनूपपुर। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमें जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझना होगा तथा जल संरक्षण को जन-जन का अभियान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक-एक बूंद को बचाकर ही हम धरती को तृप्त रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करा सकते हैं। जल संरक्षण से खेतों, कुओं, हैंडपंपों तथा अन्य जल स्रोतों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम औढेरा में नवीन तालाब स्थल पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान- 2026 के जिला स्तरीय समापन एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उक्ताशय के विचार व्यक्त किए।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा चैत्र प्रतिपदा एवं हिंदू नववर्ष के अवसर पर 19 मार्च से प्रारंभ किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान आज 30 जून को एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जिले के विभिन्न विभागों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के अनेक कार्य किए हैं। इस दौरान तालाबों का निर्माण, नदी-नालों की सफाई, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन तथा जलग्रहण क्षेत्रों का विकास जैसे सराहनीय कार्य संपादित किए गए हैं। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जल संरक्षण का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे प्रयासों को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि शासन की अपेक्षा है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर जन आंदोलन का स्वरूप धारण करे। प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि जल हमारे जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता था, किंतु वर्तमान समय में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। शासन का दायित्व है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित और जागरूक किया जाए।

श्री जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में वर्षा जल संचयन (वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वर्षा का जल भूमि में समाहित होकर भू-जल स्तर को बढ़ाने में सहायक हो सके। उन्होंने कहा कि भू-जल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण जल का अत्यधिक दोहन तथा जल पुनर्भरण की अपर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पवित्र नगरी अमरकंटक से निकलने वाली मां नर्मदा देश के विशाल भूभाग को हरित, समृद्ध एवं ऊर्जावान बना रही है। इसलिए प्रत्येक गांव में स्थित नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। मंत्री श्री जायसवाल ने इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का वाचन किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह ने कहा कि आज हम सभी 19 मार्च से 30 जून तक प्रदेशभर में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 'जल ही जीवन है' और हमारी नदियां, तालाब तथा बावड़ियां हमारी संस्कृति एवं जीवन का आधार हैं। यह अभियान केवल सरकारी स्तर पर संचालित होने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनसहयोग और जनभागीदारी के माध्यम से जल संरचनाओं को नया जीवन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के सहयोग एवं श्रमदान से ग्राम पंचायत ओढेरा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है, जो सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि अभियान के दौरान जिन जल संरचनाओं का पुनर्जीवन किया गया है और जल संरक्षण के महत्व को जिस प्रकार समझा गया है, उसे हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने जल संचयन एवं संरक्षण व संवर्धन के संबंध में जनमानस का आव्हान करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियां की जानकारी दी उन्होंने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताओं एवं जनहित करी प्रावधान के संदर्भ में आमजन को अवगत कराया। कार्यक्रम को जिला पंचायत उपाध्यक्ष पार्वती राठौर तथा बृजेश चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया।

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्प अर्पण से किया गया कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत के पीआरओ अमित श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों तथा नागरिकों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह, उपाध्यक्ष पार्वती राठौर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

ओढेरा के नवीन तालाब परिसर में हुआ पौधारोपण

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियो अधिकारी कर्मचारियों पत्रकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने ग्राम औढेरा के नवीन तालाब परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया।

आपको बताते चलें

आज जिला स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह में मंच में लगे बड़े-बड़े बैनरो में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल की फोटो नदारत रही,यह कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा, आयोजक चाहते तो एक बैनर में मंत्री श्री जायसवाल की फोटो लगाकर एक बैनर बना सकते थे? (क्योंकि कार्यक्रम के मंत्री श्री जायसवाल मुख्य अतिथि थे)मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया,यह मंत्री जी को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं यह कोई साजिश तो नहीं हो रही है?

राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा एवं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के तत्वावधान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान

देवास। राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा एवं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 7262 के तत्वावधान में सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके लंबे एवं समर्पित सेवाकाल के लिए सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू पहलवान सांगते, अनिल पहलवान खरे, लालचंद्र डागर,

प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश पहलवान सांगते, रूपेश कल्याणे, शहर अध्यक्ष राजेश गोसर, सुनील फतरोड, सोनू डुमाने, जितेंद्र डागर, शहर अध्यक्ष राकेश बंजारे, जिला अध्यक्ष पारस कालौशिया सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। समारोह का समापन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान एवं शुभकामनाओं के साथ हुआ।

क्या तीन दशक बाद शहडोल संसदीय क्षेत्र को मिल सकता है केन्द्र में प्रतिनिधित्व

– विंध्य- महाकौशल प्रांत का युवा जनजातीय महिला चेहरा शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह

अनूपपुर। शहडोल संसदीय क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हिमाद्री सिंह का नाम एक बार फिर तेजी से चर्चा मे है। शांत ,धीर - गंभीर ,मृदु स्वभाव, धार्मिक - आध्यात्मिक संस्कारों के साथ विनम्र भाव से प्रशंसा - निंदा के प्रति निस्पृह रहने वाली हिमाद्री सिंह की गिनती सर्वथा गैर - विवादित, सक्रिय और पार्टी विचारधारा के प्रति समर्पित सांसद के रुप मे है।

2019 और 2024 मे रिकार्ड मतों से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके दो बार सांसद निर्वाचित होने के बावजूद अपने पिता पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व दलवीर सिंह (राजीव गांधी,नरसिंह राव मंत्रिमंडल में थे)और पूर्व सांसद स्व राजेश नन्दिनी सिंह से मिली राजनैतिक - सामाजिक और संस्कार जनित विरासत का रंचमात्र भी अहंकार नहीं है।

लगभग सात वर्ष के कार्यकाल मे बडवारा और शहडोल जिले के

पुत्री के लालन - पालन और कोविड विभिषिका का कठिन समय निकाल दें तो वे निरंतर अनूपपु जिले के अमरकंटक - बेनीबारी से कटनी के जयसिंहनगर ,उमरिया के चंदिया से लेकर अनूपपुर के कोतमा,बिजुरी, वेंकटनगर तक लोगों के सुख - दुख मे शामिल होती रही हैं ।

संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों , सामाजिक गतिविधियों मे सक्रियता के अलावा केन्द्र और प्रदेश सरकार / संगठन द्वारा सौंपे गये प्रत्येक दायित्व के निर्वहन मे उनका समर्पण निर्दोष और प्रशंसनीय है।

पिछले लगभग 30 सालों मे स्व दलवीर सिंह के बाद शहडोल संसदीय क्षेत्र जैसे बडे जनजातीय क्षेत्र को केन्द्र सरकार मे प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हिमाद्री सिंह मे वह सभी खूबियां हैं जो एक कुशल , योग्य ,शिक्षित ,ईमानदार राजनेता मे होना चाहिये।

वह एक युवा,सुयोग्य,ईमानदार जनजातीय महिला चेहरा हैं। जिन्हें केन्द्र सरकार मे मंत्री बनाए जाने का दूरगामी संदेश मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ,बिहार जैसे राज्यों मे जाएगा।

मध्यप्रदेश मे सांसद हिमाद्री सिंह जनजातीय समाज का स्थापित युवा उर्जावान नेतृत्व है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र का शीर्ष नेतृत्व उनका किस तरह से सदुपयोग करता है।

चचाई को मिला आधुनिक प्री-स्कूल, द मेगामाइंड प्री स्कूल का भव्य शुभारंभ

– मुख्य अतिथि तनवीर अहमद ने किया फीता काटकर उद्घाटन, विद्यालय के विकास में हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन

अनूपपुर। चचाई क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को द मेगामाइंड प्री स्कूल का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तनवीर अहमद, Executive Director, ATPS, Chachai ने फीता काटकर विद्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अविनाश सिंह (Superintendent Engineer) सीताराम पटेल डॉ. कौशलेन्द्र सिंह एवं डॉ.वीरेन्द्र खेस उपस्थित रहे। विद्यालय पहुंचने पर नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया, जिसकी सभी ने सराहना की।

मुख्य अतिथि तनवीर अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि चचाई क्षेत्र में इस स्तर के आधुनिक प्री-स्कूल की स्थापना निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने विद्यालय परिवार को शुभकामनाएँ देते हुए भविष्य में विद्यालय की प्रगति एवं विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। समारोह में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी विद्यालय की आधुनिक सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच की प्रशंसा करते हुए इसे चचाई क्षेत्र के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विद्यालय आने वाले समय में क्षेत्र के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर नई पहचान स्थापित करेगा। कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावकों, गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु उत्कृष्ट एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने का संकल्प दोहराया।

जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत, प्रभारी कलेक्टर ने 78 आवेदनों में की सुनवाई

अनूपपुर। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी ने 78 आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याएं सुनी। ग्राम गुंवारी, तहसील जैतहरी के निवासी भगवान दीन राठौर ने बोरवेल खनन की अनुमति प्रदान किए जाने, बनगवां, तहसील कोतमा के निवासी जयराम पनिका ने मकान क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि स्वीकृत किए जाने, तथा पुरानी बस्ती, वार्ड क्रमांक-6, कोतमा के निवासी कृष्ण पाल सिंह ने गरीबी रेखा सूची में

नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार ग्राम पारसवार, तहसील अनूपपुर के निवासी छोटेलाल सिंह ने सीसीसी ऋण योजना का लाभ प्रदान किए जाने, तथा ग्राम खालेदूधी, तहसील पुष्पराजगढ़ की निवासी ओमवती ने विधवा पेंशन स्वीकृत किए जाने एवं गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़े जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, ग्राम खाड़ा, तहसील अनूपपुर के निवासी शंकर लाल बैगा ने जनमन योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने, ग्राम देवहरा, तहसील अनूपपुर के निवासी संत राम चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किए जाने, ग्राम कांसा, तहसील अनूपपुर के निवासी संत लाल यादव ने बंधवा टोला स्थित तालाब की मेढ़ का जीर्णोद्धार कराए जाने तथा ग्राम खालेदूधी,तहसील पुष्पराजगढ़ के निवासी चैन सिंह ने गरीबी रेखा सूची में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

अनूपपुर में वन अधिकार दावों के निराकरण हेतु आज चलेगा विशेष अभियान

अनूपपुर। प्रदेश के साथ-साथ अनूपपुर जिले में भी वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में निरस्त दावों के पुनः परीक्षण, लंबित दावों तथा नवीन प्राप्त व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन संबंधी दावों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चरणबद्ध एवं समयबद्ध विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) एवं सामुदायिक वन अधिकार (CFR) दावों का निराकरण नवीन एमपीएफआरए पोर्टल (mpfra.mp.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन (CFRR) से संबंधित दावों का निराकरण ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। चार माह तक चलने वाले इस विशेष अभियान से जिले के पात्र हितग्राहियों को उनके वन अधिकारों का लाभ सुलभता से उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमपी वनमित्र पोर्टल पर लंबित एवं नवीन दावों के निराकरण के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत ग्राम वन अधिकार समितियों द्वारा दावों का परीक्षण, स्थल निरीक्षण, नक्शा तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने तथा ग्राम सभा से संकल्प पारित कर दावों को उपखंड स्तरीय समिति को प्रेषित करने की कार्रवाई की जाएगी। उपखंड स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त दावों एवं अपीलों का परीक्षण एवं निराकरण कर उन्हें अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा दावों का अंतिम निराकरण किया जाएगा। स्वीकृत दावों के वन अधिकार पत्र तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे तथा हितग्राहियों को वितरित किए जाएंगे। अमान्य दावों के दावेदारों को दावा निरस्त करने के कारणों की लिखित सूचना प्रदान की जाएगी। इसके उपरांत जारी वन अधिकार पत्रों का वन एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में प्रविष्टिकरण कर वन अधिकार पत्रधारकों को अधिकार अभिलेख की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

समाजसेवी संस्था ने आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम

मुरैना। तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थान (TOFEI) अभियान के अंतर्गत धरती संस्था, जिला मुरैना द्वारा नरोत्तम सेखसरिया फाउंडेशन एवं सलाम मुंबई फाउंडेशन के सहयोग' से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोरसा में व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, विद्यालय परिसर को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाना तथा TOFEI Guidelines के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करना था।

विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती नीलम गुप्ता द्वारा कहा कि तंबाकू जैसी बुरी आदतें न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि परिवार एवं समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं नशे से दूर रहकर अपने परिवार और मित्रों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके पश्चात धरती संस्था के कार्यक्रम समन्वयक आकाश सेंगर ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को Tobacco Free Educational Institution (TOFEI) Guidelines की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाना है।

18 जिलों में होंगे नर्मदा जयंती कार्यक्रम, नदी संरक्षण से समाज को भी जोड़ें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मां नर्मदा प्रदेश की 33 प्रतिशत से अधिक आबादी की जीवन रेखा है। यह आबादी नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर ही निर्भर है। नर्मदा हमारी धार्मिक आस्था, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की आधारशिला है। इसे हर तरह से निर्मल और अविरल बनाए रख कर नर्मदा परिक्रमा पथ को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा जयंती पर विभिन्न आयोजन किए जायें। नर्मदा और इसकी सहायक नदियों सहित पूरे प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए समाज को विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि अब हर महीने नर्मदा समग्र की बैठक में इस नदी क्षेत्र के विकास के निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा समग्र की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माँ नर्मदा के विकास से जुड़ना एक पवित्र काम है। सभी विभाग के अधिकारी पूरे समर्पण से यह काम करें। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा पथ को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कर पथिकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाये और परिक्रमा मार्ग पर संकेतक (सूचना पट्टिकाएं) भी लगाए जाए। नर्मदा के तट पर स्थित सभी धार्मिक और पवित्र स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग पर जहां मंदिर हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए अन्न क्षेत्र भी स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे स्थानों पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ कराने की व्यवस्था भी कराएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे सहित अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नर्मदा समग्र से समन्वय कर नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में स्थित सभी आश्रमों की सूचियां तैयार कर लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि वे सामूहिक प्रयास कर किसानों को घाटी क्षेत्र में नकद फसलों की पैदावार लेने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि नर्मदा नदी के सीमावर्ती प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती पर आयोजन किए जाएंगे। माँ नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य, गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने बताया कि माँ नर्मदा के जल को सदैव निर्मल और अविरल बनाये रखने के लिए विभाग द्वारा 'नमन मिशन' तैयार किया गया है। यह मिशन मां नर्मदा घाटी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्राधिकृत होगा। मुख्यमंत्री इस नमन मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मिशन की साधारण सभा के उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव इस मिशन के सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मिशन के सह-सचिव होंगे। मिशन को क्रियान्वित करने के लिए इस साल 2026-27 का रोडमैप भी तैयार कर लिया गया है।

एसीएस श्रीमती रस्तोगी ने बताया कि इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए पहले से विद्यमान 3 समितियों (मंत्रिमण्डल समिति, अन्तर्विभागीय कार्यकारिणी समिति, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति) का भी सहयोग लिया जाएगा। मिशन के संचालन में जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास, वन, पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, वित्त, पर्यटन, विधि, उद्यानिकी, मत्स्य, राजस्व, जनजातीय कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, धर्मस्व, योजना एवं आर्थिकी सांख्यिकी एवं खनिज संसाधन विभाग सदस्य के रूप में तथा 10 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इस फंड के लिए 100 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राज्य अनुदान की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल ने बताया कि मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में जैव विविधता प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। इसके लिए 32 लाख रुपये का योजना प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में करीब 415 हैक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग 2.70 लाख पौधे लगायेगा।

अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में नर्मदा घाटों को निर्मल बनाये रखने की व्यवस्था की जा रही है। नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जा रहा है। नगरीय निकायों के सीएमओ को नर्मदा क्षेत्र के विकास के लिए नोडल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नर्मदा क्षेत्र के 21 नगरों में 35 एसटीपी तैयार किए जा रहे है। यह काम दिसम्बर 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर के विकास के लिए यहां स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) तैयार की जाएगी। पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि महेश्वर में 18 होमस्टे तैयार किए है और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 13 गावों में 79 होमस्टे तैयार किए गये हैं।

बैठक में पर्यावरण, धर्मस्व, राजस्व, खनिज साधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना आर्थिकी सांख्यिकी, एवं अन्य विभागों ने भी नर्मदा घाटी क्षेत्र में किए जा रहे काम की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हैः त्रिपुरा मुख्यमंत्री डॉ. साहा

भोपाल | त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से परिवर्तन और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अधोसंरचना और तकनीक सहित सभी क्षेत्रों में देश की प्रगति उल्लेखनीय है। डॉ. साहा भोपाल में एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया (AOMSI) के 28वें मिड-टर्म कॉन्फ्रेंस एवं 14वें पीजी कन्वेंशन—MIDCOMS 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जैसे विशेषज्ञता आधारित क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षण, शोध और आधुनिक तकनीकों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के सम्मेलन चिकित्सकों, विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने तथा नवीनतम उपचार पद्धतियों से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. साहा ने कहा कि त्रिपुरा में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एमबीबीएस सीटों में कई गुना वृद्धि की गई है। राज्य ने जीएसटी संग्रह, कानून-व्यवस्था एवं अन्य विकास संकेतकों में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन भी किया।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त अर्थव्यवस्था, आधुनिक अधोसंरचना, आयुष्मान भारत योजना, चिकित्सा शिक्षा विस्तार, टेलीमेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्वास्थ्य सेवाओं से देश का स्वास्थ्य क्षेत्र नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी चिकित्सा शिक्षा, सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं, ट्रॉमा केयर और आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि MIDCOMS 2026 जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन युवा सर्जनों और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, शोध और नवाचार से जोड़ते हैं। देश के वरिष्ठ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उन्हें अधिक दक्ष, आत्मविश्वासी और संवेदनशील चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित करेगा।

AOMSI के अध्यक्ष डॉ. आशीष गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। पीपुल्स ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री रोहित पंडित AOMSI के महासचिव डॉ. कलारामन बालारामन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। तीन दिवसीय सम्मेलन में देशभर से आए 1300 से अधिक ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जन, विशेषज्ञ, शिक्षकगण, स्नातकोत्तर विद्यार्थी एवं प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम शोध, आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण एवं नवाचार पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सहकारी सप्ताह के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ

भोपाल | सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का शुभारंभ गुरुवार को सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंत्री श्री सारंग ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया तथा विभिन्न सहकारी संस्थाओं, राष्ट्रीय सहकारी संगठनों, शासकीय विभागों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं उत्पादक संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित उत्पादों, नवाचारों एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रतिनिधियों से संवाद किया तथा सहकारिता आधारित आर्थिक गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में विकास, जनकल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर नए-नए प्रकल्पों पर कार्य कर रहे हैं। सहकारिता इस विकास यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तथा देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी।

सार समाचार

जनता की सुनवाई पर लगा ब्रेक

भोपाल। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन खुद धीमी पड़ती नजर आ रही है। सरकारी समीक्षा में सामने आया है कि एक लाख 77 हजार से अधिक शिकायतें ऐसी हैं, जिनका तीन माह से अधिक समय बीतने के बाद भी निपटारा नहीं हो सका। सबसे ज्यादा लंबित मामले राजस्व, गृह और नगरीय विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हैं। इन विभागों से संबंधित शिकायतें महीनों तक अटकी रहने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। यहीं नहीं 200 से ज्यादा शिकायतों को तो अटेंड भी नहीं किया गया। यही वजह है कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा दबाव राजस्व विभाग पर लंबित शिकायतों के मामले में राजस्व विभाग सबसे ऊपर है। विभाग में 1.02 लाख से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, जबकि इनमें 30 हजार से अधिक मामले ऐसे हैं, जिन्हें 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। भूमि सीमांकन, नामांतरण, खसरा सुधार और अवैध कब्जे जैसे मामलों में लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। अकेले अवैध कब्जे से जुड़ी हजारों शिकायतें अब भी लंबित हैं।

अब रिश्वतखोर ही नहीं, उनके मददगार भी कानून के शिकंजे में

भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब एक नए चरण में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। अब केवल रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके लिए रिश्वत की डील कराने वाले, रकम वसूलने वाले, नेटवर्क चलाने वाले और भ्रष्टाचार को सुविधाजनक बनाने वाले सहयोगी भी कानून के शिकंजे में आएंगे। इस नई रणनीति की शुरूआत लोकायुक्त पुलिस ने एक ऐसे मामले से की है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। लोकायुक्त का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन रिश्वत की पूरी व्यवस्था संभालता है, रकम तय करता है या वसूली करता है, तो उसे भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा। इसी कड़ी में ग्वालियर में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार महिला पटवारी रेखा शाक्य के साथ अब उसके पति कृष्णकांत शाक्य को भी सह-आरोपी बनाया गया है। यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी के परिजन को भी भ्रष्टाचार के मुकदमे में आरोपी बनाया गया है।

कृषि संकट से निपटने की तैयारी करे सरकार : कमलनाथ

भोपाल। प्रदेश में अभी तक हुई बारिश और भविष्य में मौसम विभाग द्वारा अल्प बारिश का अंदेशा बजाने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीर चिंता जताते हुए सरकार से किसानों की मदद के लिए क्या प्लान तैयार किया है को स्पष्ट करना चाहिए। नाथ ने कहा कि देश के कृषि क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि अब तक हुई अल्प वर्षा के कारण खरीफ की बुवाई 23 पिछड़ गई है और धान का रकबा 25 घटा है। अन्य खरीफ फसलों का भी यही हाल है। सोयाबीन, अरहर और मूँगफली का रकबा भी कम हुआ है। मध्य प्रदेश के करोड़ों किसान इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। हम सब की प्रार्थना है कि अच्छी बारिश हो लेकिन मौसम के पूवार्नुमानों से आँख मूँद लेना भी उचित नहीं है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि संकट में किसानों की मदद के लिए उसके पास क्या प्लान है। ऐसा न हो कि सरकार की स्थिति आग लगने पर कुआँ खोदने वाली हो जाए।

जन आंदोलन बन 7 करोड़ परिवारों तक पहुंचा जल गंगा संवर्धन अभियान

जल गंगा संवर्धन अभियान ने जनभागीदारी का रचा नया इतिहास, सोशल मीडिया पर मिली वैश्विक पहुंच

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ संचालित 'जल गंगा संवर्धन अभियान' ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के साथ देश और विदेश के लगभग 7 करोड़ परिवारों तक अपनी पहुंच बनाकर जनभागीदारी का एक नया इतिहास रच दिया है। आगामी मानसून में कम वर्षा की संभावना को देखते हुए पानी की प्रत्येक बूंद को सहेजने के दूरदर्शी उद्देश्य से शुरू हुआ यह महाअभियान 30 जून 2026 को भव्यता के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दृढ़ संकल्प से यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक विराट वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। इस महाअभियान को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला। ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के आधिकारिक

माध्यमों द्वारा प्रतिदिन जागरूकता पोस्टर, लघु फिल्में और इन्फोग्राफिक्स साझा किए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान, जल है तो कल है, #WaterConservation और #SaveWater जैसे हैशटैग्स के माध्यम से प्रदेश और देश के कोने-कोने तक जल संरक्षण का संदेश फैला, जिससे कुल 6 करोड़ 95 लाख 74 हजार 820 से अधिक लोगों तक इस अभियान की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित हो सकी और लोग जल स्रोतों को सहेजने की मुहिम से सीधे जुड़े। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सतत मॉनिटरिंग और विशेष डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से अभियान के दौरान पूरे राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर कार्य किए गए। प्रदेशभर में 10,514 करोड़ रुपये की लागत से 3 लाख 63 हजार से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण और जीर्णोद्धार के कार्य पूर्ण किए गए। भू-जल संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड समय में 67,708 खेत-तालाब, 225 अमृत सरोवर और 97,614 कूप रिचार्ज संरचनाएं तैयार की गईं। इसके अलावा 10,000 से अधिक कुओं, नदियों और प्राचीन बावड़ियों की सफाई व सौंदर्यीकरण कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इन प्रामाणिक कार्यों की बदौलत मध्य प्रदेश जल संरक्षण में देश का अग्रणी राज्य बना है। अभियान के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर श्रमदान किया और समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया। 19 मार्च 2026 को इंदौर से इसके तीसरे चरण की शुरूआत करने से लेकर धार में देवी सागर तालाब के गहरीकरण, उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, भोपाल के 'सदानीरा समागम' और राजगढ़ में आयोजित समापन समारोह तक उन्होंने सक्रिय सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संकल्प दोहराया कि 'जल है तो कल है' और सरकार इसे सहेजने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है, इसलिए जल संरक्षण के कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। अभियान के समापन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान और 1 जुलाई से विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशनर का भी भव्य शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण और जनभागीदारी के इस अभियान ने मध्यप्रदेश को देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया है। जल गंगा संवर्धन अभियान ने यह साबित कर दिया कि जब सरकार और समाज साथ आते हैं, तो जल संरक्षण केवल एक योजना नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा एक सशक्त जन आंदोलन बन जाता है।

विधानसभा के 1,336 लंबित मामलों पर सरकार सख्त

832 अपूर्ण जवाब और 298 आश्वासन अब भी अधूरे, संसदीय कार्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

भोपाल। 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सभी विभागों को लंबित विधानसभा मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य विभाग ने प्रमुख सचिवों, अपर मुख्य सचिवों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट कहा है कि विधानसभा से जुड़े मामलों का समय पर निराकरण कर जवाब उपलब्ध कराएं, ताकि सत्र के दौरान सरकार को असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 54 विभागों में कुल 1,336 मामले लंबित हैं। इनमें 832 विधानसभा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, 86 शून्यकाल के मामले, 298 मंत्रियों के अधूरे आश्वासन और 120 लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशें शामिल हैं। अधूरे जवाब सबसे बड़ी चुनौती रिपोर्ट से साफ है कि विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के 832 अपूर्ण उत्तर सबसे बड़ी चिंता का विषय हैं। इसके अलावा सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए 298 आश्वासन अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। वहीं, 120 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर भी कार्रवाई लंबित है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित है। ऐसे में संसदीय कार्य विभाग ने सभी विभागों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने और समय पर जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो और सभी विभाग समयसीमा के भीतर जवाब भेजना सुनिश्चित करें। सामान्य प्रशासन विभाग सबसे पीछे सबसे अधिक लंबित मामले सामान्य प्रशासन विभाग में जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग सबसे अधिक लंबित मामलों वाला विभाग है। यहां कुल 172 प्रकरण लंबित हैं। इनमें शून्यकाल के 5, अपूर्ण उत्तर 148, आश्वासन 18 और लोक लेखा समिति की 1 सिफारिश शामिल है। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग दूसरे स्थान पर हैं। विभाग में कुल 154 मामले लंबित हैं। इनमें 2 शून्यकाल, 126 अपूर्ण उत्तर, 16 आश्वासन और लोक लेखा समिति की 10 सिफारिशें शामिल हैं। राजस्व विभाग में 122 मामले लंबित हैं। इनमें 14 शून्यकाल, 79 अपूर्ण उत्तर, 13 आश्वासन और 16 लोक लेखा समिति की सिफारिशें शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 121 मामले लंबित हैं। इनमें 6 शून्यकाल, 60 अपूर्ण उत्तर, 46 आश्वासन और 9 लोक लेखा समिति की सिफारिशें शामिल हैं। गृह विभाग में भी 115 मामले लंबित हैं। इनमें 83 अपूर्ण उत्तर और 32 आश्वासन शामिल हैं।

इस विभाग में शून्यकाल और लोक लेखा समिति की कोई सिफारिश लंबित नहीं है। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुल 57 मामले लंबित हैं। इनमें 9 शून्यकाल, 14 अपूर्ण उत्तर, 21 आश्वासन और 13 लोक लेखा समिति की सिफारिशें शामिल हैं। समय सीमा में जवाब देने के निर्देश संसदीय कार्य विभाग ने सभी विभ गों को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो। लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाकर निर्धारित समय-सीमा में जवाब उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मानसून सत्र के दौरान लंबित मामलों की संख्या न्यूनतम रहे।

चढ़ावा चोरी में सरकार ने एसआईटी का गठन करके केवल नौटंकी की

चंपत राय के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, मामले की जांच सीबीआई को दी जाए

भोपाल। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चढ़ावा चोरी में सरकार ने एसआईटी का गठन करके केवल नौटंकी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, वे केवल चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी थे। शर्मा ने कहा कि अयोध्या में जो कार्रवाई हो रही, वह चंपत राय और उनके करीबियों को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने कहा कि इस मामले में चंपत राय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चंपत राय के इस्तीफे की चर्चा है, लेकिन इसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया। शर्मा ने सवाल उठाया कि चंपत राय को जेल क्यों नहीं भेजा गया और उनके मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। भाजपा पूरे मामले में चुप क्यों रामायण-2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने कहा कि मैं उस गूंगे शासक से पूछना चाहता हूं, जो संसद से लेकर सडकों तक कहता था कि मैं राम को लाया हूं। आज वह कहां है और इस मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास में राम मंदिर याद रखा जाएगा, तो यह भी याद रहेगा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर विवाद हुआ। यह पैसा किसानों, गरीबों और आम श्रद्धालुओं का था। भाजपा सत्ता के लालच में मूक दर्शक बनी कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद में जिस समिति को दुनिया की सबसे अच्छी समिति बताया गया था, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के लोग सत्ता के लालच में मूक दर्शक बने हुए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की कई शिकायतें हुईं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विक्रम मस्ताल ने कहा कि मैं मांग करता हूं कि न्यायालय इस मामले का संज्ञान ले।

|| संपादकीय ||

पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, मगर गला यहां के 'शांति दूतों' का क्यों सूख रहा है?

पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस दृढ़ता के साथ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखानी शुरू की है, उससे इस्लामाबाद की सत्ता, सेना और वहां के कथित लोकतांत्रिक चेहरे बुरी तरह बौखला गए हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान की नसों में ऐसा डर भर दिया है कि वहां के नेता लगातार धमकियां दे रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहे हैं और दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उनके अस्तित्व पर हमला कर दिया है।

देखा जाये तो दशकों तक भारतीयों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब पानी की कमी होने पर कांप रहा है और वहां के नेता गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु पाकिस्तान की जीवनरेखा है और भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपने पानी, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। पाकिस्तान के जलवायु मंत्री मुसद्दिक मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि जो हाथ उनके पानी को छुएंगे, उन्हें काट दिया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाते हुए आक्रामक बयान दिए। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने दुनिया को डराने की कोशिश की कि यदि सिंधु जल संधि नहीं बची तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की पूरी विश्व व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी।

लेकिन पाकिस्तान के इन आंसुओं के पीछे छिपा सच पूरी दुनिया जानती है। पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां से आए थे? जम्मू-कश्मीर में दशकों से आतंकवाद को कौन पालता रहा है? भारत के सैनिकों और नागरिकों का खून बहाने के लिए हथियार, प्रशिक्षण और धन कौन देता रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके यह स्पष्ट कर दिया कि अब नई दिल्ली पुरानी नीति पर नहीं चलेगी। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति बनाए रखेगा तो उसे हर मोर्चे पर कीमत चुकानी होगी। भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपने अधिकार वाले जल के उपयोग को तेज करने का फैसला किया है। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि अपने अधिकारों का प्रयोग है।

साथ ही सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो भारत में बैठकर पाकिस्तान से वार्ता की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक सौ से अधिक तथाकथित बुद्धिजीवियों, नेताओं और सामाजिक हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, दूतावास सामान्य करने और यहां तक कि कश्मीर पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। इस पत्र पर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और कुछ अन्य भारतीय हस्तियों के हस्ताक्षर भी हैं।

इन लोगों से देश पूछना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? जो देश भारत में आतंकवादी भेजता है, हमारे नागरिकों की हत्या करवाता है, सीमा पार से गोलियां चलाता है, उसी देश के लिए इनके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उमड़ती है? भारत ने जब पाकिस्तान का पानी रोकने की दिशा में कदम उठाया तो प्यास पाकिस्तान को लगी, लेकिन गला यहां बैठे तथाकथित शांति दूतों का सूखने लगा। आखिर क्यों? क्या इन लोगों को भारत की सुरक्षा से ज्यादा चिंता पाकिस्तान की खेती और उसकी बिजली व्यवस्था की है?

ये लोग कहते हैं कि वार्ता ही समाधान है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर कितनी वार्ताएं हो चुकी हैं? लाहौर बस यात्रा से लेकर आगरा शिखर वार्ता तक और उफा से लेकर शरम अल शेख तक भारत ने हर बार शांति का हाथ बढ़ाया। बदले में मिला क्या? कारगिल, संसद हमला, मुंबई हमला, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम। पाकिस्तान हर बार वार्ता की मेज पर मुस्कुराता है और पीठ पीछे आतंकियों को भेजता है।

आज जब भारत पहली बार कठोर नीति पर डटा है तो देश के भीतर बैठे कुछ लोग बेचैन हो उठे हैं। उन्हें आतंकवाद पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान का पानी रुकने पर दर्द होने लगता है। उन्हें भारत के शहीदों की चिंता कम और इस्लामाबाद की परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। यह वही मानसिकता है जिसने दशकों तक भारत को कमजोर नीति में बांध कर रखा।

सच यह है कि सिंधु जल संधि का सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान ने उठाया। भारत ने वर्षों तक उदारता दिखाई, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहा। अब जब नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक और व्यापार, आतंक और वार्ता, आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, तब पाकिस्तान दुनिया भर में सहानुभूति जुटाने निकला है। लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि समस्या की जड़ कहां है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पानी को लेकर युद्ध जैसे बयान देने वाले पहले अपने घर की हालत देखें। वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है और सेना तथा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रही हैं।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नया भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम भी उठाएगा। आतंकवाद को पालने वालों को अब हर क्षेत्र में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान यदि वास्तव में शांति चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद की फैक्टरी बंद करनी होगी। जब तक उसकी धरती से भारत विरोधी आतंक जारी रहेगा, तब तक कोई भी वार्ता केवल छलावा मानी जाएगी।

बहरहाल, भारत की जनता अब भ्रम में नहीं है। देश समझ चुका है कि शांति की सबसे पहली शर्त सुरक्षा है। और जो लोग पाकिस्तान के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल अब कोई नहीं कर सकता। नया भारत अपने सैनिकों के खून का हिसाब भी लेगा और अपने पानी का अधिकार भी बचाएगा।

केजरीवाल जैसा उदाहरण दोबारा ना बने, इसके लिए बड़ा विधेयक लाने की तैयारी में मोदी सरकार, 30 दिन जेल में रहे तो जायेगी पीएम, सीएम और मंत्री की कुर्सी

> सूत्रों के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट में उस विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रख सकती है, जिसके तहत किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाया जा सकता है।

गंभीर अपराधों में गिरफ्तार मंत्रियों को 30 दिन की लगातार हिरासत के बाद पद से हटाने से जुड़े संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त संसदीय समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अपनाने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार इस विधेयक को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रही है। सरकार का मानना है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री लंबे समय तक जेल में रहते हुए पद पर बना रहता है तो शासन व्यवस्था प्रभावित होती है और जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। हम आपको याद दिला दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब उन्होंने जेल से ही सरकार चलाई थी। देखा जाये तो ऐसी स्थितियां लोकतांत्रिक जवाबदेही और सुशासन की भावना के विपरीत हैं, इसलिए इस तरह की परिस्थितियों को रोकने के लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है।

सूत्रों के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट में उस विवादास्पद प्रावधान को बरकरार रख सकती है, जिसके तहत किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाया जा सकता है। हालांकि समिति इस कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर सावधानी संबंधी सुझाव भी दे सकती है ताकि राजनीतिक बदले की भावना से इसका इस्तेमाल न हो सके। माना जा रहा है कि समिति अपनी सिफारिशों में ऐसे सुरक्षा उपाय जोड़ सकती है जिनसे केवल गंभीर और स्पष्ट मामलों में ही यह प्रावधान लागू हो।

माना जा रहा है कि यह विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है और उसी दौरान इस विधेयक पर चर्चा तथा पारित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष अगस्त में यह विधेयक संसद में पेश किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसे विधेयक के विभिन्न

पहलुओं की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया था। भौगोलिकसंदर्भ

समिति की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों और सत्तापक्ष के बीच तीखा मतभेद देखने को मिला। कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन इंडिया के अधिकांश सदस्यों ने समिति की बैठकों का बहिष्कार किया। विपक्ष का आरोप था कि समिति में सत्तारुढ़ दल का बहुमत होने के कारण उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और समिति केवल औपचारिक मंजूरी देने वाली संस्था बनकर रह जाएगी। विपक्षी नेताओं का कहना था कि ऐसे माहौल में भागीदारी का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है।

वहीं सत्तारुढ़ गठबंधन से जुड़े सदस्यों ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया। उनका तर्क है कि प्रस्तावित कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था या संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है। विपक्ष का कहना रहा है कि केवल हिरासत के आधार पर किसी जनप्रतिनिधि को दंडित करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले ही मंत्री को पद से हटाया जाना अनुचित माना जा सकता है। इसके जवाब में सत्तापक्ष के सदस्यों ने दलील दी कि लगातार 30 दिन की हिरासत के दौरान संबंधित व्यक्ति को कम से कम तीन बार जमानत मांगने का अवसर मिल सकता है। इसलिए यह कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता।

सूत्रों के मुताबिक समिति के कई सदस्य, चाहे वह सत्तापक्ष से हों, विपक्ष से या तटस्थ दलों से, इस बात पर सहमत हैं कि विधेयक में ऐसे प्रावधान जोड़े जाने चाहिए जिनसे कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि किन प्रकार के अपराधों पर यह कानून लागू होगा, इसके लिए स्पष्ट सीमा या मानक तय किए जाएं। माना जा रहा है कि केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई हो जहां अपराध अत्यंत गंभीर हो और जिसकी सजा पांच वर्ष या उससे अधिक की हो। सरकार

बताया जा रहा है कि विपक्षी सांसद समिति की रिपोर्ट पर असहमति टिप्पणी भी दर्ज करा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि विधेयक को लेकर राजनीतिक सहमति अभी दूर दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि समिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों का प्रभाव अधिक है, लेकिन इसमें अन्य दलों के सदस्य भी शामिल हैं। इनमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले तथा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी भी शामिल हैं।

प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार यदि किसी मंत्री पर ऐसा अपराध दर्ज हो जिसकी सजा पांच वर्ष या उससे अधिक हो और वह लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहे, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्री को पद से हटाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि 30 दिन की हिरासत पूरी हो जाती है, तो 31वें दिन स्वतः पद समाप्त होने का प्रावधान भी रखा गया है।

हम आपको यह भी बता दें कि इस विधेयक के समर्थक यह भी तर्क दे रहे हैं कि इसका उद्देश्य केवल कानूनी जवाबदेही तय करना नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को ठप होने से बचाना भी है। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब उन्होंने जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था। आम आदमी पार्टी ने उस समय कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि उस दौर में दिल्ली सरकार के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार सवाल उठे थे। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने तक दिल्ली में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठकें नहीं हो सकीं थीं जिससे प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुए और इसका असर सीधे जनता पर पड़ा था। इसी तरह तमिलनाडु में भी वी. सेंथिल बालाजी का मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना था। धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद भी वह लंबे समय तक मंत्री पद पर बने रहे और जेल में रहते हुए सरकार का हिस्सा माने जाते रहे। विधेयक के समर्थकों का कहना है कि ऐसे उदाहरण बताते हैं कि यदि कोई जनप्रतिनिधि लंबे समय तक हिरासत में रहता है तो शासन व्यवस्था, जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था जरूरी मानी जा रही है। इतिहास

बहरहाल, यह विधेयक अब केवल कानूनी प्रस्ताव भर नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक जवाबदेही, प्राकृतिक न्याय और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बीच संतुलन को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। संसद के आगामी मानसून सत्र में इस पर होने वाली चर्चा से यह तय होगा कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और अधिकारों के बीच संतुलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

• नीरज कुमार दुबे

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

चंदा-चढ़ावा कांड 'बेनतीजा'

उप्र के पुलिस महानिदेशक रहे डॉ. विक्रम सिंह और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा के आकलन हैं कि राम मंदिर चंदा-चढ़ावा चोरी का मामला शायद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, क्योंकि जांच के नाम पर जो किया जा रहा है, उसमें कई छिद्र हैं और वह सवालिया भी है। बड़ी आरामदेह जांच चल रही है। जांच के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। अहम और संदेहास्पद सवाल यह है कि जिन 8 आरोपितों को पुनः 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, उनकी रिमांड पुलिस ने क्यों नहीं मांगी? यदि रिमांड नहीं है, तो आरोपितों से पूछताछ, सवाल-जवाब कैसे किए जाएंगे? पूछताछ नहीं होगी, तो कथित अपराधियों से बरामदगी कैसे होगी? अपराध के सुराग और नेटवर्क कैसे खुलेंगे? बरामदगी तभी महत्वपूर्ण और कानूनी है, जब आरोपित कबूल करें और खुलासा करें कि चोरी का धन, आभूषण आदि कहां रखे हैं? पैसे का कहां निवेश किया गया है? जब तक ये जानकारियां पुष्ट, सत्यापित नहीं होंगी, तब तक अपराध साबित नहीं किया जा सकता। ये दोनों शीर्ष पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जो कार्रवाई ट्रस्ट ने की और करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी विशेष जांच टीम से भी छिपाई और प्राथमिकी 20 दिन के बाद दर्ज कराई गई, इन सबके बीच इतने छिद्र हैं कि जांच किसी निष्कर्ष या नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद क्षीण है। गौरतलब है कि विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुलासा किया है कि बीती 5 जून को राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद प्राथमिक जांच कराई। पुलिस की मदद ली गई और आरोपित अविनाश शुक्ला के घर से करीब पांच लाख रुपए नकदी का काला बैग बरामद किया गया, लेकिन 7 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल ने 'चोरी' से इंकार किया। कहा कि कुछ उल्लेखनीय बात नहीं हुई।

पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह इसे ट्रस्ट की 'गैर-कानूनी' हस्तक्षेप मानते हैं। पुलिस किसके आदेश पर उस छापेमारी में शामिल हुई? उनका सवाल है कि रुपए बरामद होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई? दरअसल हमारा भी यह मानना है कि पहली बरामदगी और 25 जून को प्राथमिकी दर्ज कराने के बीच 20 लंबे दिनों का फासला था। उस दौरान आरोपितों और उनके आकाओं ने सबूत मिटा दिए होंगे, चोरी की रकम ठिकाने लगा दी होगी और उसके बावजूद अयोध्या पुलिस ने आरोपितों को रिमांड पर नहीं लिया, तो जाहिर है कि जांच का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या चंदा-चढ़ावा चोरी का इतना संवेदनशील, भ्रष्ट मामला 'बेनतीजा' भी रह सकता है? साफ लगता है कि ट्रस्ट के स्तर पर बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, लिहाजा अपराध में बराबर की भूमिका चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा आदि की भी है! पुलिस ने चंपत राय से भी पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और न ही उन्हें आरोपित करार दिया गया है। क्यों? आश्चर्य यह है कि पुलिस ने 8 आरोपितों के घर पर छापेमारी की। नकदी, आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा भी किया जा रहा है।

आरोपितों के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। फिर भी अदालत में पुलिस ने आरोपितों की रिमांड क्यों नहीं मांगी? क्या पुलिस सब कुछ जानती है? क्या पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं? हमें तो राजनीतिक दबाव, आरोपितों को संरक्षण, सांठगांठ का मामला लगता है। 'बड़ी मछलियां' डर रही होंगी कि ये 'छोटी मछलियां' कहीं सच न उगल दें और 'मगरमच्छ' जाल में न फंस जाएं! गौरतलब यह भी है कि प्रभु श्रीराम के मंदिर में व्यापक, अनवरत चोरी की जाती रही, उसकी जांच तो अभी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन का मुद्दा उछाल दिया है। उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लपेटने की कोशिश की गई है।

टेक्नोलॉजी

व्हाट्सऐप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल पर भी सरकार की नजर, हो सकता है एक्शन

व्हाट्सऐप यूजरनेम फीचर पर जारी विवाद के बीच टेलीग्राम और सिग्नल भी सरकार की राडार पर आ गए हैं. इन दोनों प्लेटफॉर्म पर पहले से ही यूजरनेम का फीचर मिल रहा था. अब आईटी मंत्रालय दोनों को नोटिस भेजकर इस फीचर को लेकर जवाब मांग सकता है. सरकार यह जानना चाह रही है कि इस फीचर में यूजर की असली पहचान कैसे सुनिश्चित की जाती है. साथ ही यह भी कि कोई व्यक्ति फर्जी नाम या किसी दूसरे की पहचान से अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह या ठगी तो नहीं कर सकता.

व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर पर लग चुकी है रोक - यूजर प्राइवेसी के लिए व्हाट्सऐप जिस यूजरनेम फीचर को ला रही थी, लेकिन उसके रोलआउट से पहले ही उस पर रोक लग गई है. सरकार ने मेटा से इस फीचर को रोलआउट न करने का कहते हुए नोटिस भेजकर तीन दिनों में जवाब मांगा है. सरकार ने फ्रॉड और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी के मामलों के डर से इसके खिलाफ सख्ती बरती है. इसके जवाब में व्हाट्सऐप ने कहा कि अभी यह फीचर रोलआउट नहीं किया जा रहा है और उसने इसमें कई सुरक्षा उपाय किए हैं. व्हाट्सऐप ने अभी इस फीचर के लिए यूजरनेम रिजर्व करना शुरू किया था.

जनरल नॉलेज

शहरों में क्यों बढ़ रहा नाइट हीट स्ट्रेस, इसकी वजह एसी या आपका अपना घर?

भारत के बड़े शहरों में गर्मियों की रातें अब वैसी राहत नहीं देती जैसी पहले देती थी. सूरज डूबने के बाद भी तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है. इस वजह से लोगों को आराम से सोने में मुश्किल होती है. वैज्ञानिक स्टडी से यह पता चलता है कि रात में बढ़ती गर्मी की वजह कोई एक चीज नहीं है. दरअसल यह कंक्रीट की इमारत, खराब शहरी योजना, कम होती हरियाली और एयर कंडीशनर के बढ़ते इस्तेमाल का मिला-जुला असर है.

गर्मी को रोकने वाली हीट ट्रैप - रात में बढ़ते तापमान की सबसे बड़ी वजहों में से एक है आधुनिक घरों के बनने का तरीका. दरअसल ज्यादातर शहरी इमारतें कंक्रीट, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील से बनती हैं. ये सभी चीजें दिनभर सूरज की गर्मी को सोखती हैं और रात में धीरे-धीरे उसे छोड़ती हैं. सूरज डूबने के बाद ठंडा होने के बजाय घर जमा हुई गर्मी को बाहर निकालते रहते हैं. इस वजह से घर के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है.

वेंटीलेशन की समस्या - तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से इमारतें एक दूसरे के काफी पास बन रही हैं. हालांकि ज्यादातर घरों में खिड़कियां होती हैं लेकिन अक्सर हवा के सही तरह से आने जाने की व्यवस्था नहीं होती. ताजी हवा के लगातार बहाव के बिना घर के अंदर की गर्म हवा अंदर ही फंसी रह जाती है.

हरियाली की कमी - पारंपरिक घरों में घर के अंदर के तापमान को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करने के लिए अक्सर मिट्टी का प्लास्टर, छायादार आंगन, मोटी दीवार और आसपास के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन आधुनिक इमारतों में आमतौर पर ठंडक देने वाली यह खूबी नहीं होती. कंक्रीट की खुली छत, पेड़ की कमी और ग्रीन रूफ न होने की वजह से इमारत दिन में ज्यादा गर्मी सोखती है और सूरज डूबने के बाद धीरे-धीरे उसे छोड़ती है.

एयर कंडीशनर का ज्यादा इस्तेमाल - हालांकि एयर कंडीशनर घर के अंदर की जगह को ठंडा करते हैं लेकिन वे अंदर से निकाली गई गर्मी को अपने कंडेंसर यूनिट के जरिए बाहर भेजते हैं. जब अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स, बाजार और रिहायशी इलाकों में हजारों एयर कंडीशनर एक साथ चलते हैं तो आसपास के माहौल में छोड़ी गई गर्मी बाहर के तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा देती है.

अर्बन बाउंड्री लेयर का असर - वैज्ञानिक रातें ज्यादा गर्म होने की एक और बड़ी वजह अर्बन बाउंड्री लेयर को बताते हैं. दरअसल रात के समय हवा की निचली परत ज्यादा स्थिर हो जाती है. इस वजह से गर्म हवा आसानी से ऊपर नहीं उठ पाती. यही वजह है कि इमारत, सड़क, गाड़ी और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी हवा में फैलने के बजाय जमीन के पास ही फंसी रह जाती है.

भारत ने धड़ाधड़ खोल दिए दुलहस्ती बांध के सारे गेट, पाकिस्तान की उड़ी नींद!

एजेंसी नई दिल्ली

सिंधु जल संधि (IWT) पर लगातार रो रहे पाकिस्तान की नींद उड़ने जा रही है। भारत ने जम्मू-कश्मीर में महत्वाकांक्षी दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट खोल दिए है। इससे चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चिनाब नदी पर 260 मेगावॉट की दुलहस्ती पावर परियोजना के दूसरे चरण को बीते साल ही मंजूरी दी थी। उस वक्त भी पाकिस्तान ने नई दिल्ली सिंधु जल संधि का उल्लंघन का आरोप लगाया था। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट खुले, चिनाब में बढ़ा पानी समाचार एजेंसी आईएएनएस ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया-'जम्मू-कश्मीर में दुल्हस्ती पावर प्रोजेक्ट के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे नदी के किनारों, जलधाराओं और निचले इलाकों से दूर रहें, क्योंकि गाद (सिल्ट) हटाने के काम के दौरान पानी के बहाव में अचानक तेजी आ सकती है। सिंधु जल को लेकर इस्लामाबाद की युद्ध वाली टिप्पणी के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर इस समझौते को लेकर भारत को धमकी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि इस्लामाबाद उन हाथों को 'काट देगा' जो सिंधु जल पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।

'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मलिक ने दावा किया, 'एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री एक नल को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पाकिस्तान की तरफ पानी की एक बूंद भी नहीं बहने देंगे।' पाकिस्तान के कई न्यूज़ आउटलेट्स ने मलिक के बयानों के क्लिप दिखाए, जो ऑनलाइन भी सामने आए। मलिक का यह बयान पाकिस्तान की उस धमकी के एक हफ्ते आया है, जिसमें उसने दशकों पुराने सिंधु जल समझौते (IWT) को लेकर 'युद्ध करने' की बात कही थी। नई दिल्ली ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से इस समझौते को रोक रखा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस महीने की शुरुआत में ARY न्यूज़ से बात करते हुए कहा था, 'जिस पल हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक हिस्सा है खतरे में है, हम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। निश्चित रूप से।' बीते साल दुलहस्ती परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दुलहस्ती परियोजना के कारण इस्लामाबाद अक्सर नई दिल्ली पर सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने और पानी को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। भारत चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की 'दुलहस्ती स्टेज-II' पनबिजली परियोजना को आगे बढ़ा रहा है। पिछले साल की शुरुआत में सिंधु जल संधि (IWT) को कुछ समय के लिए रोकने के भारत के फैसले के बाद यह प्रोजेक्ट भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव का एक नया कारण बन गया है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक अहम एक्सपर्ट पैनल ने मंजूरी दी थी। भारतीय अधिकारी इस प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से सही और 'रन-ऑफ-द-रिवर' स्कीम बताते हैं जिसका मकसद ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। वहीं पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध करता आया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और इलाके में अस्थिरता पैदा कर रहा है सिंधु जल संधि के पूरे विवाद के केंद्र में चिनाब नदी है, जो उन तीन पश्चिमी नदियों में से एक है जिनका पानी 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।

बीते साल, अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उस संधि के सस्पेंड होने के बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से अटकी कई पनबिजली परियोजनाओं (हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स) को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया था। इनमें से 'दुलहस्ती स्टेज-II' सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है। दुलहस्ती स्टेज-II प्रोजेक्ट कोई अलग से शुरू किया गया प्रोजेक्ट नहीं है। इसे मौजूदा दुलहस्ती स्टेज-I हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के विस्तार के तौर पर प्लान किया गया है। स्टेज-I 390 MW का 'रन-ऑफ-द-रिवर' प्रोजेक्ट है जिसे 2007 में शुरू किया गया था और इसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) चलाता है। स्टेज-I हर साल 2,000 मिलियन यूनिट से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है और यह उत्तरी पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है। यह जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जैसे फायदा उठाने वाले राज्यों और इलाकों को पीक-टाइम में बिजली सप्लाई करता है। असली दुलहस्ती प्रोजेक्ट का प्लान 1985 में बनाया गया था और उसी साल इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसके पूरा होने के सफर में बार-बार देरी हुई और लागत भी बढ़ती गई। दुलहस्ती बांध 70 मीटर ऊंचा और 186 मीटर लंबा है, जिसे हिमालय के ऊबड़-खाबड़ इलाके में बड़े शहरी केंद्रों से दूर बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट चिनाब नदी से पानी को 9.5 किलोमीटर लंबी हेडरेस टनल के ज़रिए पावर स्टेशन तक ले जाता है और फिर उसे वापस नदी में छोड़ देता है। इसमें निचले स्तर पर गेट वाले स्पिलवे लगे हैं जिनसे गाद (silt) को बाहर निकाला जा सकता है; हिमालयी नदियों में भारी मात्रा में तलछट (sediment) होने के कारण यह एक जरूरी सुविधा है। दुलहस्ती स्टेज-II को इसी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरह से नया बांध बनाने के बजाय, नया स्टेज, स्टेज-I पावर स्टेशन से पानी लेगा। इसके लिए 3,685 मीटर लंबी और 8.5 मीटर व्यास वाली एक अलग टनल बनाई जाएगी।

इजराइल ने निभाई यारी, भारत गदगद, अजरबैजान हैरान

एजेंसी तेल अवीव

कल तक जो अजरबैजान पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर भारत के आंतरिक मामलों पर जहर उगल रहा था, आज उसकी हालत उस चूहे जैसी हो गई है जो खुद के बनाए बिल में ही फंस गया है। आज अजरबैजान को एक नहीं बल्कि दो-दो मोर्चों पर ऐसा रणनीतिक तमाचा पड़ा है कि बाकू से लेकर इस्लामाबाद तक मातम का माहौल है। एक तरफ भारत के वो कमजोर नस दबा दी है जिसे छूने की हिम्मत पिछले 100 सालों से किसी ने नहीं की थी। इजराइल की संसद और सरकार ने एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाया है जिसे तुर्की और अजरबैजान के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। दरअसल इजराइली सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1915 के अर्मेनिया नरसंहार यानी अर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता दे दी है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। पिछले कई दशकों से इजराइल इस मुद्दे पर चुप था क्योंकि अजरबैजान उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इजराइल को अपनी ऊर्जा जरूरतों का 40% तेल अज़रान से मिलता था और बदले में इजराइल उसे हथियार देता था। लेकिन जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन किया और अजरबैजान ने पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखाई तो इजराइल ने अपनी रणनीति बदल दी। विदेश मंत्री गिदोन सार ने स्पष्ट कहा कि इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करने में अब और देरी नहीं की जा सकती है। 15 लाख अर्मेनियाई लोगों की हत्या को मान्यता देकर इजराइल ने अजरबैजान और तुर्की के उस ईगो को कुचल दिया है जिसे वह पूरी दुनिया में छिपाते फिर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटुमन साम्राज्य यानी आज का तुर्की ने सुनियोजित तरीके से अर्मेनियाई ईसाइयों का कत्लेआम किया था। 24 अप्रैल 1915 को शुरू हुए इस खूनी खेल में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सीरिया के तपते रेगिस्तानों में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया। तुर्की और उसका छोटा भाई यानी अजरबैजान आज तक इस सच्चाई को दुनिया से छिपाते आए हैं। लेकिन अब इजराइल, अमेरिका और रशिया और जर्मनी जैसे 32 बड़े देशों ने इसे जेनोसाइट मान लिया है। इजराइल का यह फैसला अज़रबैजान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चेकमेट है क्योंकि अब वह दुनिया के सामने नैतिक रूप से अकेला पड़ गया है। वैसे दोस्तों इस ग्लोबल शतरंज का असली खिलाड़ी तो भारत है। भारत ने अज़रान को उसकी सही जगह दिखाने के लिए साइलेंट वॉरफेयर का रास्ता चुना। साल 2020 के युद्ध में जब अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोंस की मदद से आर्मेनिया को नुकसान पहुंचाया तब भारत ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया और आज भारत अर्मेनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद हथियार सप्लायर बन चुका है।

जापान की प्रधानमंत्री भारत पहुंची, इंडो-पैसिफिक से लेकर AI-सेमीकंडक्टर तक कई अहम समझौतों पर नजर

एजेंसी नई दिल्ली

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची बुधवार शाम तीन दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पालम स्थित हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है और इसे भारत-जापान संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यह दोनों देशों के बीच होने वाला 20वां वार्षिक शिखर सम्मेलन भी है, जिसमें रक्षा, इंडो-पैसिफिक, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और नई तकनीकों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस यात्रा का महत्व ऐसे समय में बढ़ गया है जब पश्चिम एशिया में अस्थिरता और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर क्षेत्रीय रणनीतियां तेजी से बदल रही हैं। भारत और जापान की बातचीत का सबसे बड़ा फोकस ओपन, फ्री, और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक होगा। जापान ने इस वर्ष अपनी नई इंडो-पैसिफिक नीति पेश की है, जिसमें पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और चीन से बढ़ते तनाव पर अधिक जोर दिया गया है। भारत को इस रणनीति का प्रमुख साझेदार माना जा रहा है। दोनों देश आर्थिक सुरक्षापर संयुक्त घोषणा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहयोग पर संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं। भारत और जापान करीब 10 समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं, ऊर्जा सुरक्षा , बायोगैस, तेल एवं गैस क्षेत्र में अपस्ट्रीम विकास, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, बैटरी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं, नेक्स्ट जेनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा ओडिशा में जापानी सहयोग से विकसित हो रही ग्रीन अमोनिया परियोजना पर भी विशेष चर्चा होने की संभावना है। रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर भी जोर हाल के महीनों में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाया है। मई में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाजों को ईंधन उपलब्ध कराया था। ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। 2 जुलाई को आयोजित होने वाले बिजनेस फोरम में 100 से अधिक जापानी उद्योगपति हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई कारोबारी समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।

प्रधानमंत्री के लिए विशेष सम्मान

जापान की प्रधानमंत्री का गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा।

टाइमलाइनः कब क्या होगा?

1 जुलाई (बुधवार): शाम 7:00 बजेः नई दिल्ली आगमन (एयर फोर्स स्टेशन, पालम)

2 जुलाई (गुरुवार): सुबह 10:00 बजेः राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत

11:30 बजेः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता (हैदराबाद हाउस)

1:10 बजेः समझौतों का आदान-प्रदान और संयुक्त प्रेस वक्तव्य

3:00 बजेः भारत-जापान बिजनेस फोरम (ताज पैलेस)

3 जुलाई (शुक्रवार): सुबह 11:00 बजेः टोक्यो के लिए प्रस्थान

भारत को बहुत बड़ा झटका, चीन में 200 रूसी सैनिकों की सीक्रेट ट्रेनिंग, पुतिन के करीबी ने दी थी मंजूरी

एजेंसी मॉस्को

रूस चीन सैन्य संबंधों पर हुए बड़े खुलासे ने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। एक गोपनीय दस्तावेज से पता चला है कि रूसी सेना ने पिछले साल चीन में गुप्त सैन्य ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले रक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर मंजूरी दी थी। इस ट्रेनिंग में कम से कम चार रूसी और चीनी जनरल शामिल थे। इस दौरान चीनी सेना की देखरेख में रूसी सैनिकों को रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों और उनसे बचाव के लिए तीन हफ्तों तक ट्रेनिंग दिया गया। हालांकि, चीन ने इनकार किया है कि उसने रूसी सेना को मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और चीन एक दूसरे के बेहद करीब आए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ट्रेनिंग में इतने उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों (जनरल) की भागीदारी ने एशिया से लेकर यूरोप तक चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट में एक गोपनीय रूसी दस्तावेज के आधार पर बताया गया है कि अगस्त 2025 में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने एक आंतरिक आदेश में चीन में सैनिकों की ट्रेनिंग का जिक्र किया था। इसमें कहा गया था कि बेलौसोव के फैसले के अनुसार, रूसी सशस्त्र बलों का एक प्रतिनिधिमंडल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की सुविधाओं में ट्रेनिंग अभ्यास में भाग लेने के लिए चीन गया था। उसी रिपोर्ट में ट्रेनिंग कोर्स में से एक के बारे में जानकारी भी दी गई है। इसमें लिखा है कि, रूसी सैनिकों ने नवंबर में बीजिंग में एक मिलिट्री फैसिलिटी में रेडियोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सुरक्षा पर केंद्रित तीन सप्ताह के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया था। एक दूसरी रिपोर्ट में रूसी सैनिकों की तस्वीरें दिखाई गईं और उनके बारे में बताया गया, जिसमें वे एक चीनी इंस्ट्रक्टर से लेक्चर सुन रहे थे, एक न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडल देख रहे थे। इस दौरान उन्हें केमिकल रिकॉनसेंस, रेडिएशन रिकॉनसेंस और वेंटिलेशन सिस्टम को प्रदूषण से बचाने के तरीकों के बारे में भी सिखाया गया। चीन ने रूसी सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। हालांकि, रूस और चीन के रक्षा मंत्रालयों ने इस रिपोर्ट पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, "संबंधित आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।" उसका यह भी कहना है कि यूक्रेन संकट पर उसका रुख एक जैसा रहा है। चीन का यह भी कहना है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तटस्थ है और खुद को शांति मध्यस्थ के तौर पर पेश करता है। रूस और चीन के बीच सैन्य संबंधों के मजबूत होने से सबसे बड़ा झटका भारत को लगा है। भारत आज भी 60 प्रतिशत से ज्यादा रूसी सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करता है।

ऐसे में भारत को आशंका है कि इन सैन्य उपकरणों तक चीन की पहुंच हो सकती है।

इसके अलावा संकट के समय चीन के साथ संबंधों के कारण रूसी सैन्य उपकरणों की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।

अमेरिका-सऊदी अरब अब दोस्त नहीं? ईरान को लेकर विवाद, ट्रंप प्रशासन की रियाद को धमकी

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसकी पुष्टि खुद अमेरिकी अधिकारियों ने की है। उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर टकराव हुआ था। इस कारण ट्रंप प्रशासन को होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का मिशन रोकना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि सऊदी अरब के इस फैसले से अमेरिका इतना बौखलाया कि उसने रियाद को अंजाम भुगतने की धमकी तक दी थी। अमेरिका ने सऊदी अरब को मिसाइल इंटरसेप्टर और ड्रोन की बिक्री रोरने की धमकी दी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महत्वकांक्षी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन के लिए अमेरिका को अपने बेस और एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में, ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए जरूरी इंटरसेप्शन सिस्टम न देने की धमकी दी, जिससे रियाद को पीछे हटना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस घटना के बाद, अमेरिका सऊदी अरब में अपनी कुछ सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है और इसके बजाय उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्होंने युद्ध के दौरान ज्यादा मदद की थी। सऊदी अरब ने शुरू से ही ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका पर दबाव डाल रहा था। सऊदी अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की थी। बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि जब ट्रंप ने इस सलाह को नजरअंदाज कर 'ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू किया, तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे इस पर पुनर्विचार करने को कहा, क्योंकि इस कदम से ईरान नाराज हो सकता था। अरब अधिकारियों के अनुसार, सऊदी अरब ने पहले भी चिंता जताई थी कि अमेरिका के साथ उसके संबंधों का कोई ठोस असर नहीं दिख रहा है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था।

भारत के दो पड़ोसियों में जंग की आहट, सीमा पर गोलीबारी जारी, कभी भी छिड़ सकता है युद्ध

एजेंसी काबुल

भारत के पड़ोस में एक नया युद्ध आकार लेता दिखाई दे रहा है। यह युद्ध पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो सकता है। दोनों देश पिछले कई महीनों से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ये हमले इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर झड़पें तो आम बात है। इस कारण दोनों देशों के संबंध निचले स्तर पर हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दोनों देश कभी भी युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। इस युद्ध में एक तरफ पाकिस्तान की भारी-भरकम फौज है तो दूसरी तरफ रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को मात देने वाला अफगान तालिबान। मंगलवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान सीमा के लॉन्च किए गए चार साधारण ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ये ड्रोन बलूचिस्तान में घुसे थे। वहीं, तालिबान ने दावा किया है कि उसने ड्रोन का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने का भी दावा किया है। हालांकि, पाकिस्तान ने चंद लोगों के घायल होने की बात स्वीकारी है। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान के सरनान में एक ड्रोन हमले में दो लोग घायल हुए हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले किए हैं। तालिबान प्रशासित इस्लामिक अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने बलूचिस्तान प्रांत के सरनान में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के एक सेंटर और खैबर पख्तूनख्वा में कई अन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं, पाकिस्तान ने तालिबान के दावों को खारिज किया है। इस बीच पाकिस्तान ने तालिबान के अंदर हमले कर 36 लोगों की हत्या की है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी कैंप पर हमले किए, जबकि तालिबान का कहना है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे। 27 जून को कराची में सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े गुट 'जमात-उल-अहरार' को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तीन प्रांतों पक्तिया, पक्तिका और कुनार में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने हवाई अभियानों के दौरान कम से कम 25 चरमपंथियों को मार गिराया और साथ ही हथियारों और गोला-बारूद के बड़े भंडार को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में जीमीनी ऑपरेशन भी चलाया, जहां उसने जमात-उल-अहरार के चार सदस्य के मारे जाने का दावा किया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी सेना के हमले में उसका एक कमांडर, खान फ़रोश उर्फ जबुल मारा गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है और तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। तालिबान-पाकिस्तान संबंधों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। एक समय पाकिस्तान, तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था। अगस्त 2022 में काबुल पर तालिबान के कब्जे को पाकिस्तान ने अपनी जीत और भारत के हार के रूप में प्रचारित किया। इसके बाद तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते चले गए। आज हालात इतने खराब हैं कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान प्रशासन में अफगानिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, जो उसके देश में हमले कर रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट में बवाल, डेब्यू ना होने पर दिग्गज बोला - वो मैदान की छत...

नई दिल्ली, एजेंसी | आज नहीं तो कल वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया डेब्यू जरूर होगा. देश-विदेश के दिग्गज खिलाड़ी इस 15 वर्षीय बल्लेबाज की खुलकर तारीफ जो कर चुके हैं. वैभव को लेकर क्रिकेट जगत फिलहाल 2 गुटों में बंटा हुआ है. एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि वैभव को सब्र रखना चाहिए और कोशिश करें कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहकर खूब सारी चीजें सीखें. दूसरी ओर वह लोग हैं जो तुरंत वैभव को भारतीय टीम की जर्सी में खेलते देखना चाहते हैं.

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री भी वैभव को तुरंत डेब्यू का चांस देने के पक्ष में हैं. उनका कहना है की वैभव को आयरलैंड सीरीज में मौका दिया जाना चाहिए था और वह गेंद को इतनी बुरी तरह मारता कि बॉल मैदान की छत पर चली जाती.

रवि शास्त्री ने कहा, 'उसे आयरलैंड में मौका मिलना चाहिए था. वह छोटा मैदान था और वैभव बॉल को मैदान की छत पर पहुंचा देता. उसे वहां खेलना चाहिए था. मुझे नहीं पता उसे यहां (इंग्लैंड) मौका मिलेगा. टीम मैनेजमेंट उसे यहां शायद मौका ना दे, लेकिन वैभव का जल्द से जल्द डेब्यू होना चाहिए. IPL में उसने सबको पीटा है, कोई गेंदबाज उनसे नहीं बचा है.'

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि वह इतनी तूफानी शुरुआत करते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी राहत मिलेगी और टीम बड़े-बड़े स्कोर बना सकेगी.

एक तरफ अभिषेक शर्मा यूके टूर पर 3 पारियों में 108 रन बना चुके हैं, दूसरे छोर पर संजू सैमसन तीन पारियों में केवल 6 रन बना पाए हैं. सैमसन की असफलता को देखते हुए उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है. सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को दूसरा ओपनिंग स्लॉट दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है.

बेल्जियम का चमत्कार! 2-0 से पिछड़ने के बाद एक्स्ट्रा-टाइम में सेनेगल को 3-2 से रौंदकर क्वार्टर फाइनल में मारी एंट्री

नई दिल्ली, एजेंसी | फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में फुटबॉल इतिहास की सबसे यादगार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वापसी देखने को मिली है। सिएटल के खचाखच भरे स्टेडियम में बेल्जियम ने एक समय पर हारी हुई बाजी को पलटते हुए एक्स्ट्रा-टाइम के बेहद रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-2 से शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बेल्जियम ने शान से क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच के असली हीरो यूरी टिएलेमैन्स रहे, जिन्होंने स्टॉपेज-टाइम के आखिरी सेकंडों में पेनल्टी को गोल में बदलकर अपनी टीम को चमत्कारी जीत दिलाई।

सेनेगल ने 2-0 की मज़बूत बढ़त बनाने के बाद ज़्यादातर समय मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। हबीब डियारा ने 25वें मिनट में गोल करके खाता खोला; उन्होंने बेल्जियम के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाने के बाद करीब से गोल किया। इस्माइला सार ने दूसरे हाफ की

शुरुआत में 51वें मिनट में गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया। उन्होंने डिफेंस की गलती का फायदा उठाया और अफ्रीकी टीम को मज़बूत स्थिति में पहुँचा दिया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, वे अगले दौर में पहुँचने के प्रबल दावेदार लग रहे थे।

हालाँकि, बेल्जियम ने हार नहीं मानी। लंबे समय तक सेनेगल के डिफेंस को तोड़ने में संघर्ष करने के बाद, उन्हें रेगुलर टाइम के आखिरी मिनटों में उम्मीद की किरण दिखी। रोमेलु लुकाकू ने 86वें मिनट में करीब से गोल करके बेल्जियम की टीम में उम्मीद जगाई। ठीक तीन मिनट बाद, बेल्जियम ने रेगुलर टाइम में ही शानदार वापसी की। बॉक्स में आए एक लो क्रॉस ने सेनेगल के डिफेंस में अफरा-तफरी मचा दी और टिएलेमैन्स ने सबसे तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए 89वें मिनट में मैच को 2-2 से बराबर कर दिया, जिससे मैच एक्स्ट्रा-टाइम में चला गया।

टिएलेमैन्स ने एक्स्ट्रा-टाइम में स्कोर 3-2 किया

एक्स्ट्रा-टाइम शुरू होने तक मैच का रुख पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन सेनेगल ने काउंटर-अटैक से खतरा पैदा करना जारी रखा और थिबाउट कोर्टुआ को कई अहम बचाव करने पड़े। दोनों टीमों में थकान के बावजूद बेल्जियम लगातार आगे बढ़कर निर्णायक गोल की तलाश में जुटा रहा।

खास बात यह है कि निर्णायक पल एक्स्ट्रा-टाइम के स्टॉपेज-टाइम में आया, जब बॉक्स में फाउल के बाद VAR ने दखल दिया। रेफरी हेक्टर मार्टिनेज ने 122वें मिनट में बेल्जियम को पेनल्टी दी, जिससे सेनेगल की टीम हैरान रह गई। इस बीच, भारी दबाव के बावजूद टिएलेमैन्स ने 120+5वें मिनट में शांत मन से गेंद को टॉप कॉर्नर में पहुँचा दिया।

सेनेगल ने आखिरी सेकंडों में ज़ोरदार कोशिश की लेकिन बराबरी का गोल नहीं कर सके, और बेल्जियम ने अपनी बढ़त बनाए रखते हुए शानदार जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब उनका मुक़ाबला USA या बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में से जीतने वाली टीम से होगा। उनमें इन दोनों टीमों को हराने की क्षमता है, इसलिए सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने का मौका मिल सकता है।

6 ने इस्तीफा दिया तो एक को हटाया गया, फीफा विश्व कप के बीच 7 मैनेजर की छुट्टी हो चुकी

नई दिल्ली, एजेंसी | फीफा विश्व कप 2026 में अभी राउंड ऑफ 32 के मुकाबले ही चल रहे हैं। 48 टीमों के टूर्नामेंट में 16 टीमें ग्रुप स्टेज से बाहर हो गईं। 10 टीमों का सफर समाप्त हो चुका है। यानी अभी तक कुल 26 टीमें बाहर हुई हैं। इन 26 टीमों में से 7 के मैनेजर की छुट्टी हो चुकी है। फुटबॉल में टीम के हेड कोच को ही मैनेजर कहा जाता है। इसमें 6 ने खुद पद छोड़ा है तो एक को हटा दिया गया है। हम आपको सभी के बारे में बताते हैं।

मार्सेलो बिएल्सा- उरुग्वे - 70 साल के मार्सेलो बिएल्सा उरुग्वे के मैनेजर थे। टीम दो बार की फीफा विश्व कप विजेता है लेकिन इस बार ग्रुप राउंड से ही बाहर हो गई। टीम को इस बार एक भी जीत नहीं मिली और इसकी वजह से बिएल्सा ने अपना पद छोड़ दिया।

स्टीव क्लार्क- स्कॉटलैंड - दिग्गज फुटबॉलर रहे स्टीव क्लार्क 2019 से स्कॉटलैंड के मैनेजर थे। स्कॉटलैंड ने हैती को हराया लेकिन ब्राजील और मोरक्को से हार गई। तीसरे स्थान पर रहने के बाद भी वह नॉकआउट में नहीं पहुंच सकी। इसके बाद स्टीव ने इस्तीफा दे दिया।

होंग म्युंग बो- साउथ कोरिया - ग्रुप ए में साउथ कोरिया ने चेक रिपब्लिक के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत की थी। लेकिन फिर मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई। इस हार की वजह से टीम ग्रुप राउंड से बाहर हो गई। इसकी वजह से देश में काफी आक्रोश था। होंग म्युंग बो ने इस्तीफा दे दिया।

रोनाल्ड कोमैन- नीदरलैंड्स - फीफा विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स की टीम प्रबल विजेता के रूप में देखी जा रही थी। ग्रुप राउंड में टॉप पर रहने के बाद भी राउंड ऑफ 32 में टीम मोरक्को के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार गई। टीम की हार के कुछ घंटे के बाद ही कोमैन ने मैनेजर का पद छोड़ दिया।

सेबेस्टियन बेकासेसे- इक्वाडोर - साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर ने ग्रुप राउंड में जर्मनी को हराकर उलटफेर किया था। लेकिन राउंड ऑफ 32 में मैक्सिको से वह हार गई। इसके बाद टीम के मैनेजर सेबेस्टियन बेकासेसे ने अपने पद छोड़ने का फैसला किया।

मिरोस्लाव कौबेक- चेक रिपब्लिक - 74 साल के मिरोस्लाव कौबेक फीफा विश्व कप इतिहास के सबसे उम्रराज मैनेजर में एक हैं। ग्रुप ए में चेक रिपब्लिक की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। इसकी वजह से ग्रुप राउंड से ही बाहर होना पड़ा और कौबेक ने भी इस्तीफा दे दिया।

सबरी लमौची- ट्यूनीशिया - सबरी लमौची फीफा विश्व कप 2026 में हटाए जाने वाले पहले मैनेजर हैं। ट्यूनीशिया के पहले ही मैच में हार के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी टीम को अगले दोनों मैचों में भी हार झेलनी पड़ी।

अमेरिका की ऐतिहासिक जीत में चमके और विलेन बने फोलारिन बालोगुन , जिदान-रोनाल्डिन्हो वाले खास क्लब में हुए शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी | फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक बेहद रोमांचक नॉकआउट मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार (2 जुलाई, IST) को खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने बोस्निया के वर्ल्ड कप के सफर को यहीं समाप्त कर दिया।

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक बेहद रोमांचक नॉकआउट मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार (2 जुलाई, IST) को खेले गए इस मुकाबले में अमेरिका ने बोस्निया के वर्ल्ड कप के सफर को यहीं समाप्त कर दिया। हालांकि, यूएसए के स्टार स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन के लिए यह रात किसी रोलर-कोस्टर राइड जैसी रही, जहां उन्होंने गोल दागकर इतिहास तो रचा, लेकिन एक बड़ी गलती के कारण रेड कार्ड खाकर टीम की मुश्किलें भी बढ़ा दीं।

32वें मिनट में बालोगुन का एक गोल

ऑफसाइड होने के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन 45वें मिनट में उन्होंने अपने बाएं पैर से गोलकीपर निकोला वासिलज और दूर वाले पोस्ट के बीच से गेंद को नेट में डालकर इस वर्ल्ड कप में अपना तीसरा गोल किया। हालांकि, 64वें मिनट में मुहरमोविच के दाहिने टखने पर पैर रखने के कारण उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया गया। USA ने एक और गोल करके बोस्निया को हराया और राउंड ऑफ़ 16 में बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला तय किया। इस बीच, बालोगुन ने टूर्नामेंट के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है।

नॉकआउट में गोल करने और रेड कार्ड पाने वाले पांचवें खिलाड़ी बने बालोगुन

बालोगुन USA के पहले और टूर्नामेंट के इतिहास में कुल मिलाकर चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल किया और रेड कार्ड भी पाया। इससे पहले फ्रांस के जिनेदिन जिदान ने 2006 के फाइनल में यह कारनामा किया था, जबकि ब्राज़ील के पूर्व स्टार रोनाल्डिन्हो और गैरिंचा क्रमशः 2002 के क्वार्टर फाइनल और 1962 के सेमीफाइनल में इस लिस्ट में शामिल हुए थे।

इस सस्पेंशन के कारण मोनाको का यह स्ट्राइकर को-होस्ट USA के लिए राउंड ऑफ़ 16 का मैच नहीं खेल पाएगा। टीम बेल्जियम के खिलाफ एक मुश्किल मुकाबले की तैयारी कर रही है, जिसने उसी दिन सेनेगल को 3-2 से हराया था। टीम के साथी खिलाड़ी क्रिश्चियन पुलिसिक ने इस सस्पेंशन पर बात की। बुधवार को मिली 2-0 की जीत के बाद साथी खिलाड़ी क्रिश्चियन पुलिसिक ने कहा, 'सच कहूं तो, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए यह बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और अब हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उन्हें अगला मैच छोड़ना पड़ा, तो यह बहुत अजीब बात होगी।'

व्यापार

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा की चिंता! 'इलेक्ट्रिक वाहन' अपनाना अब राष्ट्रीय मिशन, चीन पर निर्भरता घटाने पर जोर

नई दिल्ली, एजेंसी | पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल के आयात पर उसकी भारी निर्भरता को लेकर चिंताओं को गहरा कर दिया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेजी से अपनाना और महत्वपूर्ण कलपुर्जों के मामले में चीन पर निर्भरता कम करना अब बेहद अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित 'विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन केंद्र बनाना' विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने की भी जरूरत है।

कपूर ने कहा, '' पश्चिम एशिया संकट के बाद यह और भी प्रासंगिक हो गया है। मैं कहूंगा कि अब हमारे देश के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना सबसे आवश्यक कार्य बन गया है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा।'' उन्होंने कहा कि यदि भारत का कच्चे तेल का आयात कम होता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रुपये की विनिमय दर में भी सुधार होगा। संकट के दौरान शेयर बाजारों के हालात पर उन्होंने कहा, '' ऊर्जा के मामले में हम बाहरी परिस्थितियों के प्रति इतने अधिक संवेदनशील हो गए हैं कि यह हम सभी के लिए अब चिंता का गंभीर विषय है। इसलिए अब यह हम सभी के लिए एक मिशन बन गया है।''

कपूर ने कहा कि पेट्रोलियम का उपयोग पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कमी लाना भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, '' पेट्रोलियम की खपत में सिर्फ पांच प्रतिशत की कमी भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है और यह तभी संभव है, जब हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें।'' उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को धीरे-धीरे अपनाया गया है। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन चारपहिया वाहनों के क्षेत्र में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। कपूर ने कहा, '' पेट्रोल की खपत सबसे ज्यादा दोपहिया वाहनों में होती है। देश में इस्तेमाल होने वाले कुल पेट्रोल का लगभग 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन ही खर्च करते हैं। इसलिए इस श्रेणी में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव लाना बेहद महत्वपूर्ण है।''

उन्होंने कहा कि हाल में घोषित दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति इस दिशा में सही कदम है। कपूर ने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, '' हमें यह देखना होगा कि चीन पर हमारी निर्भरता कैसे कम हो।'' उन्होंने कहा कि भारत के लिए आयात को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन कम-से-कम महत्वपूर्ण कलपुर्जों तथा आवश्यक खनिजों का घरेलू उत्पादन होना चाहिए, ताकि भविष्य में यदि चीन फिर से इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए तो उद्योग प्रभावित न हो।

उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग जगत को सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कपूर ने कहा कि सरकार की ओर से इस दिशा में ''तेज और लक्ष्य-आधारित'' रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा, '' अगले पांच वर्षों में देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की उपस्थिति इतनी अधिक होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि भारत में इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है।

83 साल की उम्र में होंगे गूगल से रिटायर, कौन हैं विंटन सर्फ जिन्होंने कहा- एआई एजेंट कर देंगे मजबूर

नई दिल्ली, एजेंसी | गूगल के 'चीफ इंटरनेट इवेंजलिस्ट', विंटन सर्फ 83 साल की उम्र में अगले सप्ताह रिटायर हो जाएंगे। वह अपना पद छोड़ देंगे। उनके करियर को टेक्नोलॉजी के इतिहास का सबसे प्रभावशाली करियर कहा जा रहा है। दुनिया में उनका ओहदा एक ऐसे व्यक्ति का रहा है जिन्हें 'इंटरनेट का जनक' माना जाता है। उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। विंटन सर्फ बीते 20 साल से भी अधिक समय से गूगल से जुड़े हैं। वह कंपनी के शुरुआती समय में ही आ गए थे। उन्होंने टेलीफोन से फोन, फिर स्मार्टफोन, इंटरनेट और अब एआई को टेक्नोलॉजी में उतरते हुए देखा है। एक हालिया बयान में विंटन ने कहा है कि एआई एजेंट्स कंपनियों को एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने पर मजबूर कर देंगे, जिससे सभी सॉफ्टवेयर आपस में आसानी से जुड़ सकें। Ai पर यह टेक दिग्गज क्या विचार रखता है, आइए जानते हैं।

इंटरनेट सबके हाथ में था, लेकिन एआई की ताकत कुछ लोगों के पास - विंटन सर्फ ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जहां एआई के बारे में कई बातें हुईं। चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि आधुनिक एआई मॉडल अमीरों और बड़ी कंपनियों के हाथ में सिमट रहे हैं, जबकि इंटरनेट सबके लिए बराबर था। इस पर विंटन सर्फ ने भविष्यवाणी की- एआई एजेंट्स के आने से टेक कंपनियों को उन्हीं स्टैंर्ड प्रोटोकॉल की ओर लौटना होगा, जैसे प्रोटोकॉल टेक कंपनियों के लिए बनाए गए थे।

विंटन सर्फ ने कहा कि एआई का एजेंटिक मॉडल, जिसमें अलग-अलग जगहों के कई एजेंट्स एक-दूसरे से बातचीत करेंगे, कंपनियों को एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाने पर मजबूर कर देगा जिससे सभी सॉफ्टवेयर आपस में आसानी से जुड़ सकें। विंटन की बात सही साबित होती है तो जो कंपनियां प्रोटोकॉल बनाने पर शुरुआत में काम करेंगी, उनका मार्केट में गहरा असर हो सकता है।

Ai के लिए अंग्रेजी नहीं परफेक्ट भाषा - विंटन की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में अधिकतर एआई मॉडलों को अंग्रेजी भाषा पर ट्रेन किया जाता है। इस वजह से हिंदी में बात करने पर लोगों के अधिक टोकन खर्च होते हैं, लेकिन विंटन सर्फ, एआई के लिए अंग्रेजी को परफेक्ट भाषा नहीं मानते। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉन्फ्रेंस में पैनल के सदस्यों का मानना था कि एआई एजेंट्स के बीच आपस में बातचीत करने के लिए इंसानी भाषा जैसे-अंग्रेजी ही काफी होगी।

वहीं, सर्फ का मानना है कि अंग्रेजी इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस भाषा में लचीलापन तो है, लेकिन अस्पष्टता भी है। दो एआई एजेंट्स के बीच बातचीत में सटीकता होना बहुत जरूरी है। 'बचपन के उस 'गेम' को याद कीजिए जिसमें आप किसी के कान में कुछ फुसफुसाते थे और 10 लोगों तक पहुंचते-पहुंचते वह मैसेज पूरी तरह बदल जाता था।

श्री लंका की ऐतिहासिक वापसी: आर्थिक कंगाली के 3 साल बाद विश्व बैंक ने दिया 'उच्च-मध्यम आय अर्थव्यवस्था' का दर्जा

विश्व बैंक ने श्रीलंका को उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है। यह फैसला उस आर्थिक संकट के तीन साल बाद आया है, जिसने देश को आर्थिक पतन के कगार पर पहुंचा दिया था।

नई दिल्ली, एजेंसी | तीन साल पहले इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट और कंगाली के कगार पर पहुंचे श्रीलंका ने वैश्विक पटल पर एक अभूतपूर्व वापसी की है। विश्व बैंक ने बुधवार को जारी अपनी नवीनतम वैश्विक आय वर्गीकरण रिपोर्ट में श्रीलंका को 'निम्न-मध्यम आय' वाले देशों की सूची से बाहर निकालकर 'उच्च-मध्यम आय' वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल कर लिया है। वैश्विक अर्थशास्त्र में श्रीलंका की इस सफलता को एक बड़े मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है।

अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि विभिन्न उद्योगों में व्यापक सुधार तथा पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण संभव हुई है। विश्व बैंक ने श्रीलंका को 'पुनरुद्धार की कहानी' करार देते हुए कहा, ''2022 में व्यापक आर्थिक संकट के कारण देश आर्थिक पतन के कगार पर पहुंच गया था। इसके केवल तीन साल बाद 2025 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण विभिन्न उद्योगों में सुधार और वित्तीय तथा पर्यटन सेवाओं में वृद्धि रही।''

इसमें कहा गया, ''यह पुनर्वर्गीकरण देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है, हालांकि वह निर्धारित सीमा को मामूली अंतर से ही पार कर पाया है।'' यह उपलब्धि हालिया वित्तीय संकट के बाद श्रीलंका की आर्थिक वापसी का प्रतीक मानी जा रही है। विश्व बैंक देशों को चार आय वर्गों उच्च आय, उच्च-मध्यम आय, निम्न-मध्यम आय और निम्न आय में बांटता है। यह वर्गीकरण पिछले कैलेंडर वर्ष के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के अनुमान के आधार पर किया जाता है।

इस वर्ष के संस्करण में 218 देशों को शामिल किया गया है और इसके परिणाम जून 2027 के अंत तक वैश्विक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। श्रीलंका पहली बार 2019 में उच्च-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में पहुंचा था, लेकिन बाद में आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ने और घरेलू एवं बाहरी दबावों के कारण आय स्तर में गिरावट आने से वह फिर निम्न-मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आ गया था।

सोने में 3000 की तेजी, भाव 1.47 लाख प्रति 10 ग्राम के पार

नई दिल्ली, एजेंसी | दिल्ली के सर्राफा बाजार में दो दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाते हुए पीली धातु ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमतों में 3,000 की भारी तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 1,47,500 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख और अमेरिकी डॉलर में आई कमजोरी ने घरेलू सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की मांग को दोबारा हवा दे दी है। इस तेजी से शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों की जेब पर असर पड़ना तय है।

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, बुधवार को सोने का बंद भाव 1,44,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जिसमें 3,000 रुपये (करों सहित) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त बनाए रखते हुए चांदी का भाव 5,000 रुपये उछलकर 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम (करों सहित) पर बंद हुआ। इससे पिछले सत्र में चांदी 2,35,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि सोने की मांग जहां अंतरराष्ट्रीय रैली के बाद सुधरी है, वहीं औद्योगिक और निवेश मांग के कारण चांदी लगातार मजबूत हो रही है।

अविका गौर

आईने के सामने खुद को देख रो पड़ती थीं

टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने 2009 में 'मॉर्निंग वॉक' और 'पाठशाला' जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'उय्याला जम्पला' से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ।

अभिनेत्री अविका गौर ने टीवी स्क्रीन पर मासूम 'आनंदी' बनकर घर-घर में पहचान बनाई, लेकिन एक समय उन्हें अपनी जिंदगी में खुद से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं। 30 जून 1997 को मुंबई में जन्मीं अविका गौर ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2007 में उन्होंने 'शश्श...कोई है' से छोटे रोल के जरिए टीवी डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में आए शो 'बालिका वधू' से मिली। इस शो में उन्होंने छोटी आनंदी का किरदार निभाया, जो एक बाल विवाह की कहानी पर आधारित था। उनके मासूम अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और वह बहुत जल्दी घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद अविका ने 'ससुराल सिमर का' में रोली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा लड़की की भूमिका निभाई। यह रोल उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था। इस शो ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। इसमें उनकी और अभिनेता मनीष रायसिंघन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने 2009 में 'मॉर्निंग वॉक' और 'पाठशाला' जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'उय्याला जम्पला' से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई।

एक समय ऐसा भी आया जब अविका अपने शरीर और आत्मविश्वास को लेकर संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने खुद बताया था कि एक समय वह आईने में खुद को देखकर टूट गई थीं और रो पड़ी थीं। उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया।

इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, नियमित वर्कआउट शुरू किया और अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव के जरिए उन्होंने करीब 13 किलो वजन कम किया और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने खुद को वैसे स्वीकार करना सीखा जैसा वह हैं।

इसी बीच अविका ने रियलिटी शोज जैसे 'खतरों के खिलाड़ी 9' और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें वह लीड रोल में नजर आईं। अपने करियर में अविका गौर ने कई अवॉर्ड्स हासिल किए, जिनमें आईटीए सर्टिफिकेट और एसआईआईएमए अवॉर्ड शामिल हैं।

प्राची सिंह बोलीं

'इंडस्ट्री में टिकना है तो मानसिक

टीवी इंडस्ट्री में कलाकारों को रोज नए किरदार निभाने पड़ते हैं, लंबे समय तक शूटिंग करनी होती है और हर दिन बेहतर परफॉर्म करने का दबाव भी रहता है। ऐसे माहौल में खुद को एक्टिव रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इसी मुद्दे पर अब टीवी अभिनेत्री प्राची सिंह ने आईएएनएस से विचार साझा किए हैं। इन दिनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में मंजरी उर्फ मुन्नी का किरदार निभा रहीं प्राची का कहना है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सिर्फ अच्छा अभिनेता होना काफी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत और जमीन से जुड़ा रहना भी बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा, 'परिवार और अपनी जड़ों से जुड़े रहना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है, तो एक अलग सुकुन मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान हमेशा खुद जैसा है, वैसा ही रहे। दिखावे में जीने से मन कभी शांत नहीं रहता।'

प्राची सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''यह काम बहुत चुनौती भरा है। ऐसे में मानसिक सेहत का ध्यान रखना और सही सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में बहुत धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप छोटी-छोटी बातों से परेशान होने लगेंगे, तो लंबे समय तक यहां टिक पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखना जरूरी है।''

उन्होंने कहा, 'परिवार और अपनी जड़ों से जुड़े रहना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जुड़ा रहता है, तो एक अलग सुकुन मिलता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान हमेशा खुद जैसा है, वैसा ही रहे। दिखावे में जीने से मन कभी शांत नहीं रहता। '

प्राची ने कहा, 'सफलता मिलने के बाद भी इंसान को विनम्र बने रहना चाहिए। मनोरंजन की दुनिया में जमीन से जुड़े रहना थोड़ा मुश्किल जरूर होता, लेकिन अगर इंसान व्यवहार और सोच को नहीं बदलता, तो वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। मैं चाहूंगी कि हर कलाकार सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बना रहे।''

बातचीत के दौरान प्राची सिंह ने अभिनय के तरीके के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए इमोशनल सीन्स सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। ऐसे सीन्स में मैं सोचती हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसा महसूस करती और कैसी प्रतिक्रिया देती। जब आप उस दर्द या खुशी को सच में महसूस करने लगते हैं, तभी वह इमोशन्स पर्दे पर भी सच्चे दिखाई देते हैं। यही तरीका मुझे इमोशनल सीन्स को शूट करने में मदद करता है।''

प्राची ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के सेट का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया, ''वहां काम का माहौल बहुत अच्छा है और अनुभवी कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए सीखने का शानदार मौका है। इस शो के लिए मुझे अचानक ऑडिशन भेजने के लिए कहा गया था। मैंने किरदार की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज दिया। करीब 10 से 15 दिन बाद मुझे फोन आया और बताया गया कि मेरा सलेक्शन हो गया है। यह खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इस मौके को अपने करियर का बेहद खास पड़ाव मानती हूं।''

सन् 1987 में पहली बार प्रसारित हुई रामायण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और भावनाओं का हिस्सा बन गई थी। 78 एपिसोड्स वाली इस गाथा ने हर रविवार को परिवारों को एक साथ जोड़ा और देखते ही देखते यह देश की सांस्कृतिक पहचान का अहम् हिस्सा बन गई। हनुमान और यशोमती मैया जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलने के बाद अब सोनी पल अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को और मजबूत करते हुए रामायण लेकर आ रहा है।

एक बार फिर होगा रामानंद सागर की रामायण का शंखनाद

मुंबई भारत के लोकप्रिय फ्री-टू-एयर मनोरंजन चैनल्स में से एक, सोनी पल अपने दर्शकों के लिए एक ऐसी सौगात लेकर आ रहा है, जिसने कभी सम्पूर्ण देश के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया था। रामानंद सागर की कालजयी गाथा रामायण अब 6 जुलाई से रात 8 बजे सोनी पल पर प्रसारित होगी।

सन् 1987 में पहली बार प्रसारित हुई रामायण सिर्फ एक धारावाहिक नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और भावनाओं का हिस्सा बन गई थी। 78 एपिसोड्स वाली इस गाथा ने हर रविवार को परिवारों को एक साथ जोड़ा और देखते ही देखते यह देश की सांस्कृतिक पहचान का अहम् हिस्सा बन गई। हनुमान और यशोमती मैया जैसे धार्मिक कार्यक्रमों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलने के बाद अब सोनी पल अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला को और मजबूत करते हुए रामायण लेकर आ रहा है। भगवान श्रीराम की यह प्रेरणादायक कथा दर्शकों को शांति, धैर्य और जीवन मूल्यों से जोड़ने का काम करेगी। रामायण के केंद्र में हैं भगवान श्रीराम, जो मर्यादा, करुणा और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ उनकी यह यात्रा आज भी लोगों के दिलों को छूती है और कर्तव्य, समर्पण तथा संघर्ष से डटे रहने की सीख देती है। दमदार कहानी और यादगार अभिनय से सुसज्जित यह गाथा सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक विशेष अवसर है।

सोनी पल के प्रवक्ता ने कहा, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक स्मृतियों और आस्था का हिस्सा है। यह ऐसी गाथा है, जो आज भी लोगों को जोड़ने और प्रेरित करने की ताकत रखती है। इसके प्रसारण के साथ सोनी पल एक बार फिर दर्शकों तक अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले मनोरंजन की पेशकश करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। भारत की इस कालजयी गाथा का फिर से आनंद लेने के लिए देखिए रामायण, 6 जुलाई से रात 8 बजे, सिर्फ सोनी पल पर।

अस्पताल में मना जन्मदिन

अली गोनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अस्पताल से जैस्मिन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। पहली तस्वीर में वह अस्पताल के बेड पर लेटी जैस्मिन को गले लगाते नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में जैस्मिन व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दीं।

टेलीविजन अभिनेता अली गोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री जैस्मिन भसीन के जन्मदिन पर उन्हें भावुक अंदाज में शुभकामनाएं देते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जैस्मिन को गंभीर संक्रमण (इन्फेक्शन) के कारण अपना जन्मदिन अस्पताल में बिताना पड़ा। अली गोनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अस्पताल से जैस्मिन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। पहली तस्वीर में वह अस्पताल के बेड पर लेटी जैस्मिन को गले लगाते नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में जैस्मिन व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दीं। अली ने पोस्ट में लिखा, 'हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जैस्मिन। हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी की कुछ और ही योजना थी। जन्मदिन की खूबसूरत यादें बनाने की बजाय हम अस्पताल के कमरे में हैं। तुम्हें दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल रहा। तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं हर जश्न कुर्बान कर सकता हूं। ' उन्होंने आगे लिखा, 'अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां, अच्छी सेहत, प्यार और सफलता दे। जल्दी ठीक हो जाओ, आज मेरे दिल में बस यही जन्मदिन की दुआ है। हैप्पी बर्थडे... हमेशा प्यार करता रहूंगा। '

एक अन्य पोस्ट में अली गोनी ने बताया कि वह जैस्मिन का जन्मदिन मनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

इस बीच, हाल ही में अली गोनी ने अपनी शादी की योजनाओं को लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'जब शादी करनी होगी, खुद सबको बता दूंगा। मेरे रिश्तेदार भी मेरे पीछे इतने नहीं पड़े, जितना इंस्टाग्राम पर लोग पड़े हैं। अपना-अपना काम करो, खुश रहो और रहने दो। '

अली और जैस्मिन लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है।

पानी की पर्याप्त सप्लाई न होने से वार्ड वासी हो रहे परेशान

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) तीन वार्डों के मध्य सुभाष वार्ड, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड एवं हनुमान वार्ड इन वार्डों का बड़ा हिस्सा (सीमा) स्थानीय सुभाष वार्ड दाउ के बाडा में स्थित ट्यूबवेल से संचालित होने वाली पानी (जल) की सप्लाई विगत एक सप्ताह से मंद एवं धीमी गति से हो रही है जिस कारण से वार्डवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं ज्ञात हो कि नगर के अलावा महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड का प्रतिनिधित्व स्वयं नपा अध्यक्ष करते हैं या तो उक्त समस्या उनके संज्ञान में नहीं आ सकी बहर हाल जो भी हालांकि नपा द्वारा ट्यूबवेल मोटर का सुधार कार्य कराया तो गया परंतु पुरानी ट्यूबवेल मोटर रिपेयर कर डाल तो दी गई लेकिन उसकी पर्याप्त क्षमता ना होने के कारण पर्याप्त पानी सप्लाई नहीं होने से वार्ड वासी परेशान हो रहे हैं सुधार कार्य के दौरान उक्त मोटर सुधार कर दो बार लगाई जा चुकी है फिर भी पानी की सप्लाई मोटर की पर्याप्त क्षमता ना होने के कारण परेशानी का सबक बनी हुई है। जबकि ट्यूबवेल मोटर की क्षमता 25 हॉर्स पावर की होना चाहिए उक्त ट्यूबवेल की मोटर को बदलकर नई एवं पर्याप्त क्षमता वाली अथवा 25 हॉर्स पावर की मोटर डाल कर एवं शीघ्र ही वार्ड वासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए ताकि वार्डवासिओं को राहत मिल सके वार्ड वासियों ने नपा से इस ओर ध्यान देने की पुरजोर मांग की है

गाडरवाराः शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार शर्मा सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त, गरिमामय विदाई समारोह आयोजित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) बीते दिवस शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों की सुदीर्घ परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाडरवारा के प्राचार्य सुशील कुमार शर्मा अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में गरिमामय विदाई एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षक, पूर्व विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक , अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोटरी मिनेंद्र डागा, एस.के. मिश्रा, नगरपालिका सभापति आनंद दुबे, सुरेंद्र गुर्जर एवं अनूप जैन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय परिवार ने अतिथियों का स्वागत किया तथा श्री शर्मा के लंबे सेवाकाल और विद्यालय में उनके योगदान पर आधारित स्मृतियों का प्रस्तुतीकरण किया। बालिका शिक्षा और संस्कारों को दी नई दिशा

मुख्य अतिथि श्रीमती साधना स्थापक ने कहा कि एक शिक्षक केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शर्मा ने अपने पूरे सेवाकाल में बालिका शिक्षा, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और संस्कारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिससे हजारों छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हुआ। सेवानिवृत्ति नई यात्रा की शुरुआत

अध्यक्षीय उद्बोधन में पंडित शिवाकांत मिश्रा ने कहा कि सेवानिवृत्ति किसी कर्मयोगी के जीवन का अंत नहीं, बल्कि अनुभवों के नए अध्याय की शुरुआत होती है। उन्होंने श्री शर्मा के शांत, विनम्र और कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा जगत में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रोटरी मिनेंद्र डागा ने कहा कि श्री शर्मा ने विद्यालय को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कारों का मंदिर बनाया। एस.के. मिश्रा ने उन्हें सादगी, अनुशासन और संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक समाज की अमूल्य धरोहर होते हैं। आनंद दुबे ने कहा कि शिक्षा और समाज सेवा का जो समन्वय श्री शर्मा ने अपने कार्यकाल में प्रस्तुत किया, वह अनुकरणीय है।

सुरेंद्र गुर्जर ने उनके सहज, सरल और सहयोगी स्वभाव की सराहना की, जबकि अनूप जैन ने विद्यालय के विकास और प्रशासनिक दक्षता में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया।

समारोह में विद्यालय परिवार, शिक्षकों, कर्मचारियों, पूर्व विद्यार्थियों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने श्री शर्मा का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ, स्मृति-चिह्न एवं अभिनंदन-पत्र भेंट कर सम्मान किया।

अपने संबोधन में श्री सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा उनके लिए केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का मिशन रही है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवनभर मिला स्नेह और सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ मानवीय मूल्यों और संस्कारों का विकास करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और उपस्थित नागरिकों ने श्री शर्मा के स्वस्थ, सुखमय एवं सक्रिय जीवन की कामना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी।

शिक्षक अशोक कौरव को सेवानिवृति पर दी विदाई

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) गत दिवस चीचली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुड़ारी के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक अशोक कौरव के अर्धवार्षिकीय सेवा अवधि पूर्ण होने के अवसर पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मे उन्हें शिक्षकों एवं ग्रामवासियो ने शाल, श्रीफल, विदाभिनंदन पत्र एवं उपहार देकर विदाई दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोविंद सिंह पटैल ने श्री कौरव के कार्यकाल को प्रशंसनीय बताया। जिला पंचायत सदस्य सुश्री मोना कौरव ने कहा कि समाज में शिक्षक का पद हमेशा सम्मानीय होता है। बीआरसी डी के पटैल ने कहा कि श्री कौरव ने इस विद्यालय में लम्बे समय तक सेवाएं दी। अंत में श्री कौरव ने अपने उदबोधन में सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षक भीकम सिंह कौरव ने किया। कार्यक्रम मे विभिन्न संकुलो से आये शिक्षक एवं श्री कौरव के परिजन सहित अन्य उपस्थित रहे

लीनेस क्लब दिव्य शक्ति ने किया डॉक्टर्स डे एवं सीए डे पर सम्मान समारोह आयोजित

• साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा

गाडरवारा। (राजेश नीरस) लीनेस क्लब द्वारा डॉक्टर्स डे एवं सीए डे के अवसर पर शासकीय चिकित्सालय गाडरवारा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. डी. एस. चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि शासकीय चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. उपेंद्र वस्त्रकार तथा डॉ. बबीता सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लीनेस क्लब अध्यक्ष नम्रता वसा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं लीनेस सदस्य शिखा नीखरा द्वारा ध्वज वंदना के साथ किया गया।

स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष नम्रता वसा ने कहा कि चिकित्सक मानव जीवन की रक्षा के लिए निरंतर समर्पित रहते हैं, वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर डॉ. अनामिका जैन, डॉ. आशुतोष मेहता, डॉ. बबीता सिंह, मुख्य अतिथि डॉ. डी. एस. चौधरी तथा सी,ए अभिषेक मंगवानी एवं देवेश जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सेवा, निष्ठा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह में उपस्थित चिकित्सकों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया।

कार्यक्रम का सफल संचालन लीनेस मंजू गुप्ता ने किया। समारोह में लीनेस सदस्य किरण साहू, सुषमा जैन, मंजू खंताल, रेखा मेहरा, सुनीता वर्मा एवं सपना सोनी, रेवती जैन की सक्रिय सहभागिता रही। अंत में सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए तथा स्नेहभोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सचिव रेखा मेहरा ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों, सीए एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज थारवानी, डॉ आशुतोष मेहता डॉक्टर अभिनव जैन डॉक्टर अनामिका जैन, डॉक्टर डीपी पंथी, डॉ शिवम् ढिमोले, डॉक्टर परितोष जैन,डॉक्टर विनीत जैन , होम्योपैथिक डॉक्टर रूबी जैन जो एनटीपीसी में 7 साल से अपनी सेवाएं दे रही है, डॉ अंजलि जैन एवं उपस्थित सभी डॉक्टर्स सी,ए, श्रेयांश कटहल आदर्श व्यवहार, देवेश जैन अभिषेक मंगतानी, अंकित शर्मा को उनकी सेवा समर्पण के लिए क्लब द्वारा सम्मानित किया गया ।

दिसंबर तक चलेगी जबलपुर - अयोध्या स्पेशल ट्रेन

साधना एक्सप्रेस रीवा

पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर - अयोध्या धाम जक्शन जबलपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की आबादी दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है इससे दोनों दिशाओं में 24- 24 अतिरिक्त फेरे संचारित हुए जाएंगे जिसे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी रेलवे के अनुसार गाड़ी संया धाम जक्शन जबलपुर अब अपने निर्धारित ठहराव समय सारणी और को संरचना के अनुसार ही चलेगी सतना से इस ट्रेन में हर फेयर करीब 500 यात्री सफर करते हैं 21 जुलाई से बड़ी अवधिः गाड़ी संया 01705 जबलपुर - अयोध्या धाम (हर मंगलवार) जो पहले 14 जुलाई तक अधिसूचित थी अब एक 21 जुलाई से 29 दिसंबर तक संचालित होगी इस अवधि में ट्रेन के 24 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे इसी तरह गाड़ी संया 01706 अयोध्या धाम जंक्शन - जबलपुर (हर बुधवार) जो पहले 15 जुलाई तक अधिसूचित थी अब 22 जुलाई से 30 दिसंबर तक चलेगी।

स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य भी समय पर नहीं हो सका प्रारंभ

आंगनवाड़ी केंद्रों के पास भवन नहीं शाला पूर्व कक्षा संचालन में बाधा।

साधना एक्सप्रेस रीवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केदो में संचालित की जा रही शाला पूर्व (प्री स्कूल) कक्षाओं के संचारु संचालन में भावनाओं की कमी बड़ी बाधा बन रही है जिले के कई आंगनबाड़ी केंद्र आज भी स्वयं के भवन से वंचित है जबकि उनके लिए भवन स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका है इसका सीधा असर नैनी हालों की प्रारंभिक शिक्षा और समुचित देखभाल पर पढ़ रहा है रीवा जिले में 98 तथा मऊगंज जिले में 13 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है भवन स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण एजेंसियों की धीमी कार्य प्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण परियोजनाएं कागजों तक सीमित है

वर्तमान में अनेक आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत भवन सामुदायिक भवन किराए के कमरों अथवा अन्य वैकल्पिक स्थान से संचालित हो रही है ऐसे स्थान पर बच्चों के लिए पर्याप्त जगह सुरक्षित वातावरण और आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है इससे साल पूर्व शिक्षा की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और पोषण के लिए आंगनबाड़ी केदो का स्वयं का भवन होना आवश्यक है भवन नहीं होने से खेल आधारित शिक्षण पोषण कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के प्रभावी संचालक में कठिनाइयां आती हैं स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित और सुविधा युक्त वातावरण में सालपुर शिक्षा उपलब्ध हो सके साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसियों की जवाब दे ही भी तय किए जाने की आवश्यकता जताई गई है।

संभाग में निर्माणाधीन भवन ।

जिला	स्वीकृत	कार्य प्रारंभ नहीं
रीवा	189	98
सतना	257	135
सीधी	96	52
मऊगंज	23	13
मैहर	45	35
सिंगरौली	58	49

नोट – गत वर्ष स्वीकृत भावनाओं में कुछ जगह निर्माण अंतिम चरण में है कई जगह शुरू ही नहीं हुआ।

बरसात में कक्षाओं का संचालन होगा मुश्किल।

तीन से 6 वर्ष आयु के बीच के बच्चों को आंगनबाड़ी केदो में पटना बरसात की दिनों में मुश्किल हो जाएगा अभी जहां पर भावनाओं की समस्याएं वहां पेड़ों के नीचे या अन्य जगहों पर बैठाया जा रहा है

बरसात के दिनों में सुरक्षित स्थान तलाशना भी कठिन कर हो जाएगा इसकी शिकायतें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी तक पहुंच चुकी है इसके बावजूद वैकल्पिक अवस्थाओं पर ध्यान नहीं है।

पोषण ट्रैकर में 70 हजार पंजीयन।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों का पंजीयन पोषण ट्रैकर पोर्टल पर किया जा रहा है रीवा जिले में 70 हजार 778 बच्चों का पंजीयन हो चुका है जबकि यहां पर कॉल अनुमानित संख्या 13 19 84 है विभाग की दवा है कि पंजीयन की संख्या अधिक है पोर्टल पर जल्द ही नया डाटा अपडेट हो जाएगा

इसी तरह मऊगंज जिले में 2682 6 सीधी में 62064 सतना में 60932 मैहर में 295 और सिंगरौली में 545 74 से अधिक पंजीयन हुआ है इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश के पहले आंगनबाड़ी केदो में खेल-खेल में शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा

साल में प्रवेश के समय आंगनबाड़ी केदो में उत्सव के साथ बच्चों को स्कूलों के लिए भेजने का कार्यक्रम भी इस साल शुरू किया गया है।

रीवा कमिश्नर ने मऊगंज में ली समीक्षा बैठक

एएनसी पंजीयन और पोषण स्तर सुधारने की दी हितायत।

साधना एक्सप्रेस मऊगंज

रीवा संभाग के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने मऊगंज कलेक्ट्रेट संभाकक्ष में बुधवार को समीक्षा बैठक ली बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं विकास कारों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ले उन्होंने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए

कमिश्नर ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखें और आमजन की समस्याओं का चरित्र निराकरण प्राथमिकता से करें समीक्षा के दौरान कृषि विभाग को खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक भंडारण ई विकास पोर्टल से खाद वितरण और किस रजिस्ट्री के निर्देश दिए गए

स्वास्थ्य विभाग को मातृ शिशु स्वास्थ्य एएनसी पंजीयन और पोषण स्तर सुधारने जबकि शिक्षा विभाग को नामांकन छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तक वितरण और सीएम राइस विद्यालयों की प्रगति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया कमिश्नर ने जल जीवन मिशन नल जल योजनाओं सिंचाई परियोजनाओं मनरेगा महिला एवं बाल विकास उर्जा और पशुपालन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की उन्होंने मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारी पुख्ता रखने तथा सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, मिनाक्षी पांडेय द्वारा डीके ऑफसेट प्रिंटर्स 50/6 शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से मुद्रित एवं 111/44, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र से प्रकाशित।
संपादक मिनाक्षी पांडेय एवं स्थानीय संपादक मनीष पांडेय मो.न- 7566293490, प्रबंध संपादक आशीष नेमा मेल sadhnaexpress@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र रहेगा।)| RNI NO. MPHIN/2022/84698